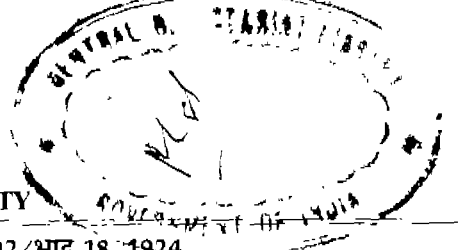




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 232 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2002/भाद्र 18, 1924

No. 232 ]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2002/BHADRA 18, 1924

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2002

अंतिम जांच परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ, ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और थाइलैण्ड के मूल की या वहां से निर्यातित पोली-आइसो-बूटिलीन के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच।

सं. 47/1/2001-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अधीन।

## क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 1: दिसंबर, 2001 की अधिसूचना सं० 47/1/2001-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ, ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर से पोली-आइसो-बूटिलीन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध पक्षकारों से इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों का अवगत कराने का अनुरोध किया था ;
- (ii) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे पक्ष की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था;

- (iii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार भेजें ।
- (iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए 28 फरवरी, 2002 को सार्वजनिक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जिसमें घरेलू उद्योग, आयातकों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से इस प्रकार प्राप्त लिखित निवेदनों पर नामित प्राधिकारी द्वारा इन निष्कर्षों पर विचार किया गया है ।
- (v) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी :
- (vi) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हें अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । परन्तु हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और/या इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है :
- (vii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए सुविचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार का ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के लिए खुलासा किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ।
- (viii) यह जांच 1 अप्रैल, 2000 से 31 अगस्त, 2001 तक की अवधि में की गई थी ।
- (ix) अधिसूचना में \*\*\*\*\* उस सूचना को दर्शाता है जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर दी गयी थी और प्राधिकारी द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया गया था ।

**ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच**

## **2. घरेलू उद्योग के विचार**

### **(i) पाटन के संबंध में**

निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल दो निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया था । यूरोपीय संघ, बीएसएफ ने मात्र तर्क दिये हैं । निर्यातक द्वारा निर्धारित फार्म में और तरीके से कोई कोई तथ्यपरक सूचना दी गयी है । कोरिया के डाइलिम को छोड़कर किसी भी अन्य निर्यातक ने

निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं भेजा है। प्रारंभिक जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन और पाटन मार्जिन का घरेलू उद्योग ने समर्थन किया है और अनुरोध किया है कि इस संबंध में प्रारम्भिक जांच परिणामों की पुष्टि की जाए। कोरिया गणराज्य के उत्तर देने वाले अन्य निर्यातक अर्थात् मै0 डाइलिम ने यह निवेदन किया है कि अपने उत्तर में निर्यातक ने उत्तर का कोई गैर-गोपनीय सारांश नहीं दायर किया है। अतः वे निर्यातक द्वारा दिये गये उत्तर और कंपनी द्वारा किये गये दावे पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने कहा है कि प्रारम्भिक जांच परिणामों से ज्ञात होता है कि निर्यातक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उक्त कंपनी द्वारा किये गये निर्यातों के संदर्भ में पर्याप्त पाटन मार्जिन था। कंपनी द्वारा दायर की गई टिप्पणियों में उस पाटन कीमत के स्पष्ट संकेत किये गये हैं जिस कीमत पर कंपनी द्वारा माल निर्यात किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब निर्यातक की घरेलू बिक्री कार्यक्षम है तब भारत के लिए निर्यात की कीमत की तुलना अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात की कीमत से करना प्रासंगिक नहीं है।

घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध भी किया है कि यूरोपीय संघ से पाटन के मामले में किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। अकेले फ्रांस से ही बहुत कम कीमत पर निर्यात हो रहा है जो गैर-हानिकर कीमत से कम है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की परम्परा के अनुसार, जहां किसी निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है, तो उन्होंने सहयोग करने वाले निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत के आधार पर उन अन्य गैर-सहयोगी निर्यातकों का पाटन मार्जिन और/अथवा क्षति मार्जिन निर्धारित कर दिया है। विद्यमान प्रकरण में, जिसमें किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है, अधिमानित औसत निर्यात कीमत की बजाय इन कम मूल्य वाले निर्यातों के आधार पर पाटन मार्जिन और/अथवा क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाएगा।

## (ii) क्षति के संबंध में

- (क) घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के अनुसार प्राप्त जानकारी से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तव में हानि हुई है।
- (ख) चूंकि नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित मानदंड पूर्णतया लागू होते हैं इसलिए भारत में सभी स्रोतों से होने वाले सामान के पाटन से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच संचयी रूप से की जानी आवश्यक है।
- (ग) संबद्ध देशों से आयात में असीमित और भारत में पोली-आइसो-बूटीलीन के उत्पादन व खपत की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।
- (घ) कुल आयात में संबद्ध देशों से आयात बाजार का हिस्सा और भारत में पोली-आइसो-बूटीलीन की मांग में वृद्धि हुई है।

- (ड.) 2 स्ट्रो इंजन आयलों में पोली-आइसो-बूटीलीन का प्रयोग अनिवार्य कर दिये जाने के कारण पोली-आइसो-बूटीलीन की मांग में भारी वृद्धि हुई है। किन्तु संबद्ध देशों के निर्यातकों ने और अधिक पाटन करना शुरू कर दिया है।
- (च) वर्ष 1999-2000 तक घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री में वृद्धि मांग बढ़ने के कारण हुई थी। किन्तु 2000-2001 में और जांच की शेष अवधि में भी बिक्री में कमी के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट आई। वास्तव में, बिक्री में भारी गिरावट ने घरेलू उद्योग को उत्पादन घटाने के लिए बाध्य किया।
- (छ) संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत, बिक्रय मूल्य और/अथवा अहानिकर कीमत से काफी कम थी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का रुख आयातित उत्पाद की ओर हो गया। घरेलू उद्योग अपना उत्पाद नहीं बेच सका, परिणामतः इस कंपनी के स्टॉक में भारी वृद्धि हुई। जब घरेलू उद्योग के गोदाम पूरी तरह भर गये और कम्पनी को माल का भण्डारण बाहरी स्थानों पर करना पड़ा, कम्पनी को माल के भण्डारण की समस्या से निपटने के लिए उत्पादन में कटौती करनी पड़ी।
- (ज) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तो बढ़ी किन्तु घरेलू उद्योग उसी अनुपात में अपना बिक्री मूल्य नहीं बढ़ा सका। इस प्रकार, आयात ने घरेलू उद्योग को कीमतों में न्यायोचित वृद्धि करने से रोका।
- (झ) आयात के कारण भारतीय बाजार में कीमतों में भारी गिरावट/मंदी रही।
- (य.) घरेलू उद्योग को गम्भीर वित्तीय घाटा उठाना पड़ा क्योंकि उत्पादन लागत वसूल करने के लिए बिक्री मूल्य पर्याप्त नहीं थे।
- (ट) घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर प्राप्ति नकारात्मक थी।
- (ठ) घरेलू उद्योग को नगदी प्रवाह की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा।
- (ड) याचिकाकर्ता का यह निष्कर्ष है कि पाटित आयात से घरेलू उद्योग को वास्तव में हानि हुई है। इसके अलावा, आयातों से और अधिक हानि होने का खतरा हो रहा था क्योंकि निर्यातकों की क्षमता बहुत अधिक है, मूल्य में बहुत अधिक कमी कर दी गई थी (जैसा कि खुली निविदा में आईओसी को प्रस्तुत की गयी कीमतों से स्पष्ट है) और आयात वृद्धि की दर अपेक्षाकृत काफी महत्वपूर्ण और अत्यधिक थीं।

(iii) अन्य मुद्दे

- क. अंतरिम शुल्क पहले ही अमेरिकी डालर में है, अतः अंतिम शुल्क भी केवल अमेरिकी डालर में ही होना चाहिए ताकि विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण सुरक्षा की मात्रा कम न हो सके ।
- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये संदर्भ मूल्य से घरेलू उद्योग को यथोचित राहत नहीं मिली इसलिए संदर्भ मूल्य की समीक्षा की जाए और इसे बढ़ाया जाए ।
- ग. प्रारंभिक जांच परिणामों में यूरोपीय संघ और थाइलैंड से होने वाले आयातों पर किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है । याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि इन देशों से निर्यात कीमत हानि के स्तर की थी । तदनुसार उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी से इन दोनों देशों के मामले में निर्यात कीमत निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध किया है जो गैर-सहयोगी निर्यातों के मामले में अपनायी जाती है, जिससे यह सिद्ध होगा कि इन देशों से भी आयात हानिकर स्तर का था ।
- घ. लुब्रीजोल द्वारा की गयी प्रस्तुतियों पर तेल कंपनियों द्वारा की गयी प्रस्तुति की तरह विचार नहीं किया जा सकता । न तो अन्य कंपनियों ने प्राधिकार दिया है और न ही लुब्रीजोल द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर अन्य कंपनियों ने हस्ताक्षर किये हैं । लुब्रीजोल तो एक तेल कंपनी भी नहीं है । इस प्रकार, तेल कंपनी के रूप में लुब्रीजोल द्वारा दी गयी समग्र प्रस्तुति तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती हैं ।
- ङ. जिन हितबद्ध पक्षकारों ने ये निवेदन प्रस्तुत किए हैं उनमें से किसी ने भी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । स्पष्ट रूप से यह इस प्रकार की जांच में भाग लेने के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग है जिसमें हितबद्ध पक्षकार वास्तविक सूचना प्रस्तुत नहीं करता है बल्कि केवल बयानबाजियों का सहारा लेता है ।
- (च) देश में उत्पाद की सम्पूर्ण मांग पूरी करने में याचिकाकर्ता अथवा घरेलू उद्योग की असमर्थता अनुचित मूल्य पर पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करना कोई पूर्वापेक्षा नहीं है । माननीय सीगेट ने अनेक जांचों में यह राय बरकरार रखी है । ईपीडीएम खंड से संबंधित अपील में माननीय ट्रिब्यूनल ने यह माना था कि यदि घरेलू उद्योग जरूरत अर्थात् मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं होती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय बाजार में सामग्री के पाटन की अनुमति दी जानी चाहिए ।
- (छ) भारतीय उद्योग भारत में पीआईबी की वास्तविक मांग की पूर्ति कर सकता है और वह बड़ी हुई मांग की पूर्ति करने की स्थिति में भी है जिससे आगे की अड़चन खत्म हो जाएगी । भारतीय उद्योग इस समय प्रतिमाह 2000 मी.टन से अधिक का उत्पादन कर रहा है जो भारत में पीआईबी की समस्त वास्तविक मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त था ।

- (ज) पीआईबी का उत्पादन करने की भारतीय क्षमता, भारत में इसकी मांग से अधिक है। भारत सरकार ने सभी 2-स्ट्रोक इंजन ऑयल में पोलि-आइसो-बुटालीन के प्रयोग को अप्रैल, 1998 से अनिवार्य बना दिया था जिसके परिणामस्वरूप भारत में पोलि-आइसो-बुटालीन की मांग में अचानक वृद्धि हुई थी। इस बात पर विचार करते हुए कि भारतीय उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए स्वयं को तैयार करने से पहले ही उन विदेशी उत्पादकों जिनकी पहले से ही उच्च क्षमता थी, ने भारतीय बाजार में इसकी बड़ी मात्रा में बिक्री करना काफी आकर्षक पाया। यद्यपि इस प्रकार के निर्यातों को अपराध नहीं माना जाता किंतु इसकी अनुमति पाटन कीमतों पर नहीं दी जा सकती है खासकर तब जब इससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता हो।
- (झ) यह तर्क कि सिंगापुर से हुए आयातों की पहुंच कीमत नुकसान रहित कीमत से अधिक है (और अतः सिंगापुर से हुए आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है), तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना से यह मालूम होता है कि सिंगापुर से जिस सामग्री का निर्यात किया जा रहा है उसकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की नुकसान रहित कीमत से कम है।
- (य.) इन हितबद्ध पक्षकारों ने बड़ी सहजता से आई ओ सी एल द्वारा जारी खुली निविदा की अनदेशी की है। संबद्ध देशों के कुछेक निर्यातकों और उत्पादकों ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जारी की गयी अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं में कीमतों का उल्लेख किया था। ट्रॉम्बे, चेन्ई और कलकत्ता में की जाने वाली सुपुर्दगियों के लिए पृथक कीमतों का उल्लेख किया गया था। 5200 मी० टन संबद्ध उत्पाद की खरीद के लिए दिनांक 27 अप्रैल, 2001 की निविदा सं० सीओएम/जीटी/आईएफ/ल्यूब जो 19 जुलाई, 2001 को खोली गई, में यह स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि इन निर्यातकों द्वारा जिन कीमतों का उल्लेख किया गया है वे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमतों और उनकी बिक्री कीमत से काफी कम थीं।
- (ट) विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों का कथन उनके अपने निवेदनों में विभिन्न स्थानों पर दिए गए निजी कथनों के विपरीत हैं। यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय उद्योग पीआईबी की मांग पूरी नहीं कर सकता है इसलिए उनके पास अधिक कीमतों पर आयात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यदि देश में उत्पाद की कमी होती तो घरेलू उद्योग अधिक स्टॉक रखने और अब भी संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं होता और न ही घरेलू उद्योग द्वारा आयातित उत्पादकी कीमत से कम कीमत वसूल की होती जैसाकि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आरोप लगाया गया है।
- (ठ) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग आयातों की पहुंच कीमत से कम कीमत पर माल बेच रहा था, सही नहीं है क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जो न्यूनतम निवेदित कीमत के आधार पर अपनी सामग्री की खरीद करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा, इन कम्पनियों ने निवेदित कीमतें भारतीय उत्पादकों से भी ली थीं। इस प्रकार के मामले में यह अविश्वसनीय है कि इन कम्पनियों ने उन कीमतों पर आर्डर दिए थे

जो न्यूनतम कीमत से अधिक थीं। स्वाभाविक रूप से, इन कम्पनियों ने आयात की पहुंच कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमतों से कम पाया था।

- (ड) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के मापदण्डों के बारे में डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के एक निर्णय का संदर्भ दिया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) की ओर ध्यान आकर्षित किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन निर्णायक कारकों को देखने की जरूरत है जो क्षति का पता लगाने में उनका मार्गदर्शन करेंगे। निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल सभी संगत मापदण्डों का मूल्यांकन करने की जरूरत है। उन मापदण्डों का जांच परिणामों में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है जो संगत नहीं हैं अथवा जो घरेलू उद्योग की राय में क्षति प्रदर्शित नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता ने नियमावली के नियम 12(और 17) का भी संदर्भ दिया है जिसमें यह उल्लेख है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति का निर्धारण करने हेतु और निर्धारण करने के मुख्य कारणों के लिए संगत विचार को दर्ज करने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के निर्णय के संबंध में याचिकाकर्ता ने यह निवेदन किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच कर रहे हैं। डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान निकाय का निर्णय निर्दिष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।
- (ढ) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की क्षमता 5500 मी० टन प्रति वर्ष की है। (जैसाकि उसके तुलन-पत्र में दिया गया है) न कि 7500 मी० टन जैसाकि याचिका में उल्लेख किया गया है। इस संबंध में यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता के संयंत्र की मैसर्स क्वार्नर पावरगैस इंडिया प्रा० लि० द्वारा पहले एक तकनीकी लेखा-परीक्षा की गई थी। इस तकनीकी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता 7500 मी० टन पीआईबी का उत्पादन कर सकता है। इसलिए याचिका में क्षमता 7500 मी० टन के रूप में ली गई है। यह उल्लेख करना भी संगत है कि 7500 मी० टन की क्षमता के स्थान पर याचिकाकर्ता की वर्ष 1999-00 में वास्तविक सर्वोत्तम उत्पादन की उपलब्धि 6111 मी० टन की थी।
- (त) बिक्री कीमत एक मापदण्ड है जो घरेलू उद्योग की क्षति से संगत है। मात्र बिक्री कीमत में वृद्धि का तात्पर्य 'कोई क्षति' नहीं है। बिक्री कीमत में होने वाली वृद्धि को उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के साथ देखा जाना है। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत में बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे की सारणी से भी स्पष्ट है :-

रूपए प्रति मी.टन	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
उत्पादन लागत	100	107.50	129.04	122.29
बिक्री कीमत	100	116.31	123.50	113.90
लाभ/हानि	100	386.67	-46.51	-143.88

टिप्पणी : सूचीबद्ध आंकड़े

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को कीमत में उचित वृद्धि करने से रोक रखा है।

श. बी आई एफ आर का संदर्भ लेना असंगत और प्रसंगेतर है। बी आई एफ आर कम्पनी का तात्पर्य यह नहीं है कि कम्पनी बन्द हो गई है अथवा अकार्यक्षम हो गयी है। यह उल्लेख करना भी संगत है कि यह कम्पनी अपने पोलि-आइसो-बुटालीन प्रचालनों के कारण बी आई एफ आर नहीं है। कम्पनी पोलि आइसो बुटालीन का दक्षतापूर्वक उत्पादन कर रही है और घरेलू बाजार में इसकी विक्री कर रही है। तथापि, बाजार को अब संबद्ध देशों के निर्यातकों से खतरा है।

ग. आयातकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. मैसर्स मोहिनी आर्गेनिक्स प्रा० लिमिटेड

मैसर्स मोहिनी आर्गेनिक्स प्रा० लि० जो कच्ची सामग्री रूप में पी आई बी का इस्तेमाल करने वाली एक लघु इकाई है, ने निवेदन किया है कि :

- (क) कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता को देखते हुए और परिष्कृत उत्पाद के लिए उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पी आई बी पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क आगे के लिए समाप्त कर दिया जाए। चूंकि पी आई बी से निर्मित अंतिम उत्पादों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता इसलिए वहां अंतिम उत्पाद के आयात की अधिक संभावना है जहां पी आई बी एक निविष्टि है। इस प्रकार इन अंतिम उत्पादों के भारतीय विनिर्माता प्रतिस्पर्धा से बाहर रहेंगे।
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत पीआईबी के विनिर्माताओं को निर्देश दिया जाए कि वे लघु क्षेत्र को सामग्री की आपूर्ति उस कीमत पर करें जिस कीमत पर वे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बहुसंख्य उपभोक्ताओं को दे रहे हैं।

- (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत पीआईबी के विनिर्माताओं को निर्देश दिया जाए कि वे लघु इकाई को उसकी जरूरतों की आपूर्ति करते रहें और उसकी नियमितता सुनिश्चित करें।

**घ. तेल उद्योग के सदस्यों का संयुक्त अभ्यावेदन**

4. तेल उद्योग के निम्नलिखित सदस्यों ने अभ्यावेदन किया है कि पॉलि-आइसोबुटालीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए :-

1. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०, मुंबई
2. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मुंबई
3. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मुंबई
4. आईबीपी कम्पनी लि०, कलकत्ता
5. कास्ट्रोल इंडिया लि०, मुंबई
6. लुब्रीजोल इंडिया प्रा० लि०, मुंबई

अभ्यावेदन में दिए गए तर्कों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

- (i) लगभग 35000 एम टी पी ए की कुल भारतीय मांग के बदले घरेलू उद्योग 18800 एम टी पी ए (90% क्षमता उपयोग पर) से 24000 एम टी पी ए (115% क्षमता पर) के बीच ही आपूर्ति कर पाया। न्यूनतम 11000 एम टी पी ए की कमी होगी जो 14120 एम टी पी ए तक जा सकती है और यह घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग पर निर्भर करेगा।
- (ii) सिंगापुर से हुए निर्यातों की औसत सीआईएफ कीमत 36.45 रुपए प्रति किग्रा. थी जो थाईलैण्ड के 35.33 रुपए प्रति किग्रा. औसत सीआईएफ कीमत से अधिक है। चूंकि सी आई एफ कीमत अधिक है इसलिए सिंगापुर से हुए निर्यातों का पहुंच मूल्य थाईलैण्ड के निर्यातों से कम नहीं हो सकता था। अतः सिंगापुर से हुए आयातों के खिलाफ लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को तत्काल वापस ले लिया जाए।
- (iii) ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत का परिकलन डीजीसीआईएस के आंकड़ों जमा एक संविदा में आई ओ सी एल की उद्धृत कीमत के आधार पर किया है। हमारी सूचना के अनुसार, आई ओ सी एल द्वारा दो निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। पहली निविदा 22.3.2000 को खोली गई थी और आर्डर जांच अवधि के दौरान दिया गया था। इस निविदा में, सिंगापुर की कीमत अत्यधिक थी और सिंगापुर को कोई आर्डर नहीं मिला। इसलिए, इस निविदा में कोई निर्यात कीमत नहीं थी क्योंकि कोई बिक्री नहीं की गई थी। दूसरी निविदा 8.6.2001 को खोली गई थी किन्तु आर्डर जांच अवधि के काफी बाद अक्टूबर, 2001 में दिया गया था। किसी तरह से इस निविदा में घरेलू उद्योग को आर्डर मिला और सिंगापुर का सूची में नाम भी नहीं है। इसलिए सिंगापुर की

- निर्यात कीमत केवल डीजीसीआईएस के आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए और उस कीमत पर पहुंच मूल्य नुकसान रहित कीमत से अधिक है।
- (iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी को क्षति के विश्लेषण में पाटनरोधी नियमों के अनुबंध II के पैराग्राफ (iv) में विनिर्दिष्ट सभी 15 कारकों का मूल्यांकन करने की जरूरत है। तथापि, इस मामले में प्राधिकारी ने 15 आवश्यक कारकों में से केवल 8 का मूल्यांकन किया है। कॉटन-टाइप बेड लिनेन मामले में भारत सरकार ने डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान निकाय के समक्ष यह तर्क दिया था कि ये सभी 15 कारक अनिवार्य हैं और यूरोपीय आयोग को इनका मूल्यांकन पाटनरोधी जांचों में करना चाहिए। डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान निकाय इस तर्क से सहमत था। और तदनुसार मामले का निपटारा किया। यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार ने उसका अनुसरण नहीं किया है जिसका उसने प्रारंभिक निष्कर्षों में स्वयं समर्थन किया है, यह दोषपूर्ण है क्योंकि प्राधिकारी ने सभी 15 कारकों का मूल्यांकन नहीं किया है।
- (v) प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार जांच अवधि के दौरान बिक्री वसूली में वृद्धि हुई है। अतः घरेलू बिक्री कीमत में जांच अवधि के दौरान गिरावट नहीं आई है और इस अवधि में कीमत का प्रभाव नहीं रहा है।
- (vi) दो अवधियों के अंत में अंतिम भंडार की तुलना करना इस कारक का सही मूल्यांकन करना नहीं है। यह मूल्यांकन उचित नहीं है। प्राधिकारी का यह निर्णय कि घरेलू उद्योग को इस घटक के कारणवश क्षति हुई है, गलत है क्योंकि प्राधिकारी ने पूरे वर्ष की औसत माल-सूची के स्टॉक पर नजर नहीं डाली है।
- (vii) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैराग्राफ 5 के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों से भिन्न किसी ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। नियमों में यह व्यवस्था है कि ऐसे कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए। अतः प्राधिकारी को क्षति का मूल्यांकन करते समय इन कारकों के प्रभाव को हिसाब में लेना चाहिए था। अतः प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करते समय उपरोक्त प्रत्येक कारक के बारे में अपेक्षित समायोजन करना चाहिए था।
- (viii) याचिकाकर्ता कम्पनी और भारत में अन्य घरेलू उत्पादकों के लागत ढांचे में व्यापक भिन्नता है। अन्य घरेलू उत्पादकों की तरह दक्षतापूर्वक कार्य करने में याचिकाकर्ता कम्पनी की असमर्थता उनकी क्षति का एक प्रमुख कारण है और इस प्रकार की अक्षमता अधिक आयातों के कारण नहीं हो सकती है।
- (ix) याचिकाकर्ता कम्पनी एक बीआईएफआर कम्पनी है। इस प्रकार की रुग्ण कम्पनी लागत भारत में उन घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधि नहीं हो सकती है जो गैर-बीआईएफआर कम्पनियां हैं।
- (x) संदर्भ कीमत का निर्धारण सीआईएफ स्तर पर किया जाना चाहिए। यदि संदर्भ कीमत का निर्धारण पहुंच कीमत के आधार पर किया जाता है और पाटनरोधी शुल्क इस संदर्भ कीमत और माल के वास्तविक पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के रूप में

लगाया जाता है तो जांच अवधि के पश्चात् सीमा शुल्क की दरों में होने वाले परिवर्तनों पर विचार नहीं किया जाता है ।

- (xi) याचिकाकर्ता अथवा घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि स्थानीय विनिर्माता जांच अवधि के दौरान और जांच अवधि के पूर्व भी 100% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहे थे ।
- (xii) आयातों का बाजार हिस्सा स्थानीय विनिर्माताओं से पोलि-आइसो बुटलीन की सही गुणवत्ता और मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । याचिकाकर्ता की अपनी कच्ची सामग्री की आपूर्ति के उचित स्रोत प्राप्त करने की असमर्थता के कारण कई अवसरों पर याचिकाकर्ता और अन्य घरेलू विनिर्माताओं ने पोलि-आइसो-बुटीलीन की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता सूचित की थी ।
- (xiii) याचिकाकर्ता ने पाटन संबंधी प्रथाओं के बारे में असंगत मुद्दा प्रस्तुत किया है जबकि पॉलि-आइसो-बुटीलीन के घरेलू विनिर्माता इस स्थिति में नहीं हैं कि वे देश की मांग पूरी कर सकें । पालि-आइसो बुटीलीन के आयातों की वजह से ही और वह भी मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से यह कहना कि निर्यातकों ने पाटन करने के कार्यों में वृद्धि की है, गलत है ।
- (xiv) याचिकाकर्ता ने यह गलत कहा है कि बिक्रियों में गिरावट आई है और इसलिए घरेलू उद्योग को उत्पादन में कमी करने के लिए माध्य होना पड़ा है । याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000-01 के दौरान पोलि-आइसो-बुटीलीन के 5745 मी० टन का उत्पादन और 5396 मी० टन की बिक्री की है जैसाकि शेरयधारकों को संबोधित निवेशकों की रिपोर्ट में कहा गया है ।

## ४. निर्यातकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार

5. कोरिया की एक निर्यातक कंपनी मै० डाइलिम इंडस्ट्रियल कंपनी लि० ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :-

- (क) इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । निर्यातक ने दावा किया है कि भारत में पी आई बी के उत्पादकों की तुलना में उन्हें अर्थव्यवस्था के मानदण्ड, उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी अपनी प्रौद्योगिकी का काफी प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त है । इस प्रकार मै० डाइलिम पोलि-आइसो-बुटिलीन की उत्पादन लागत भारतीय उत्पादकों से कम है । निर्यातक ने अनुरोध किया है कि भारतीय सीमाशुल्क का 35% छोटे संयंत्रों वाले स्थानीय पोलि-आइसो-बुटिलीन उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है । जांच अवधि के दौरान भारत को उनकी निर्यात कीमत उत्पादन लागत से लगभग 6% अधिक थी । 6% का निवल लाभ पण्य पेट्रो रसायन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की तुलना में सामान्य है, जो कि 10% के निवल लाभ से कम रहा है क्योंकि सामान्यतः पोलि-आइसो बुटिलीन एक पण्य रसायन है न कि विशेष वस्तु ।

- (ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह तय किया है कि याचिकाकर्ता की सबसे कम कीमत थी जिसके परिणामस्वरूप आई ओ सी एल द्वारा जारी निविदाओं में निर्यातकों द्वारा उद्धृत काफी कम कीमतों के कारण घरेलू उद्योग को काफी हानि हुई है। डब्ल्यू टी ओ एडीए(पाटन रोधी करार) के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार जिन वस्तुओं का दूसरे देश के व्यापार में प्रवेश हुआ है, उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए विचार किया जाता है। भारत के व्यापार में जिन वस्तुओं का प्रवेश नहीं हुआ है उन वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का परिकलन करने हेतु निविदा कीमत के प्रयोग से उम्पर उल्लिखित अनुच्छेद का उल्लंघन हो सकता है।
- (ग) जांच अवधि के दौरान नेष्ठा की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 42% की वृद्धि हुई थी। इसलिए याचिकाकर्ता को लाभ-हानि केवल उसकी अधिक उत्पादन लागत के साथ-साथ फीड स्टॉक कीमत में वृद्धि के कारण हुई थी न कि आयातित माल के कारण। उस समय डाइलिम को निवल लाभ में घाटा हुआ क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पोली-आइसो-बुटिलीन की कीमत में वृद्धि नहीं हुई थी।

#### घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है। तथापि याचिकाकर्ताओं/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच की गई है जो निम्नानुसार है :-

- (i) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू प्रतिस्पर्धा क्षति का कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क न केवल निराधार है बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों के विपरीत भी है। उपभोक्ताओं द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां मांग घरेलू उत्पादन से अधिक है, वहां आंतरिक प्रतिस्पर्धा क्षति नहीं पहुंचा सकती।
- (ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के प्रभाव को कम करने के लिए सीमित रखा गया है। जबकि यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क निर्धारण से उत्पादकों और उपभोक्ताओं की उत्पाद संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है, फिर भी, इस पर बुरी तरह प्रभाव नहीं पड़ेगा विशेषकर तब जब पाटनरोधी शुल्क की राशि उस स्तर तक सीमित रखी गई है जो घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने के लिए पूरी तरह आवश्यक मानी गई है।
- (iii) इस तर्क के संबंध में कि निविदा में दी गई पेशकश का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि आपूर्ति जांच अवधि के बाद की गई थी और नियमों में उन वस्तुओं के संबंध में कार्रवाई के लिए प्रावधान किया गया है जिनका भारत में आयात हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी कार्रवाई देश के वाणिज्य में सम्मिलित की गई वस्तुओं के विरुद्ध की जा सकती है। 'सम्मिलित' शब्द का अर्थ 'जांच

अवधि में आयातों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। निविदा में कंपनी द्वारा किया गया स्थायी तथा अपरिवर्तनीय प्रस्ताव देश के व्यापार में वस्तुओं के प्रवेश करने के समान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा निविदा में ऐसी भागीदारी और उनके द्वारा उद्धृत कीमतों के परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादकों को क्षति हुई है क्योंकि ऐसे मामलों में खरीददार आमतौर पर अपने आर्डर न्यूनतम उद्धृत कीमत के आधार पर देते हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि पाटित कीमतों पर निर्यातकों द्वारा निविदा में दिए गए ऑफर के कारण घरेलू उद्योग को ठेके की हानि हुई है और क्षति हुई है! इस तथ्य का संबंध नहीं के बराबर है कि डिलीवरी जांच अवधि के बाद की गई है।

- (iv) भारत में पोली-आइसो-बुटिलीन के अन्य निर्माताओं की तुलना में घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि से संबंधित मुद्दे के बारे में प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनी के लागत ढांचे की विस्तार से जांच की और मै0 कोठारी के साथ मै0 कोच्ची रिफाइनरीज़ की उत्पादन लागत की तुलना की गई। मै0 कोच्ची रिफाइनरी ने अपने दिनांक 26.9.2001 के पत्र के द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए :-

(क) उनके पोली-आइसो-बुटिलीन संयंत्र से वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पोली-आइसो-बुटिलीन के कुल कारोबार में लगभग 40% की निवल हानि हुई।

(ख) वर्ष 2000 के दौरान निविष्टि लागत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद जब उन्हें उत्पादन की लागत को अपनी कीमत से काफी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि संयंत्र के प्रचालन को बनाए रखने के लिए आयातित उत्पाद की पहुंच कीमत को पहुंच मूल्य के बराबर रखा जा सके।

(ग) मै0 के आर एल को भारत में प्रमुख तेल उद्योग कंपनियों द्वारा जारी की गई निविदाओं में विदेशी विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत कीमतों के समान करने के लिए वर्ष 2000 में लगभग 10% की कटौती करने को बाध्य होना पड़ा।

(घ) वर्ष 2000 में तैयार उत्पाद की कम मांग के कारण उनके संयंत्र संचालन को लगभग एक माह के लिए रोकना पड़ा।

- (v) इसके अतिरिक्त मै0 कोच्ची रिफाइनरीज़ ने सी I और सी II प्रारूप में उत्पादन की लागत का विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत किया जिससे यह मालूम हुआ कि मै0 कोच्ची रिफाइनरीज़ में उत्पादन की लागत मै0 कोठारी की पोली आइसो-बुटिलीन की उत्पादन लागत से अधिक थी। तथापि यह सूचना एन.आई.पी. का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त थी। यह भी मालूम हुआ कि इस सूचना के बाद संयुक्त अभ्यावेदन में उपभोक्ताओं ने कोच्ची रिफाइनरी के बारे में लागत के संबंध में एक अन्य ही सूचना प्रस्तुत की जो कोच्ची रिफाइनरी द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत से काफी भिन्न पाई गई। इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत का यह विवरण कोच्ची

रिफाइनरी के पी एंड एल लेखे के अनुरूप नहीं है। यदि इस उत्पादन लागत संबंधी विवरण को अंगीकार किया जाता है तो कोच्ची रिफाइनरी को लाभ होना चाहिए जबकि पी एंड एल लेखों से मालूम होता है कि कोच्ची रिफाइनरी को हानि हुई है। स्पष्टतया संयुक्त अभ्यावेदन में दावा की गई लागत कोच्ची रिफाइनरी द्वारा खर्च किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं है। यक तर्क कि उत्पादन लागत कम है को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- (vi) यह तर्क कि सिंगापुर की पहुंच लागत गैर-क्षतिकर कीमत से अधिक है, वास्तव में गलत है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान सिंगापुर से किए गए निर्यातों की पहुंच कीमत XXXX अमरीकी डालर थी जो कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई गैर-क्षतिकर कीमत से काफी कम थी।
- (vii) मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने की पूर्व शर्त नहीं है। आयात पाटनरोधी शुल्क को लगाने के बाद भी सही कीमतों पर किए जाते रहेंगे। पाटनरोधी शुल्क को लगाने से भारतीय बाजार में उत्पाद की आपूर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (viii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से मूल्यांकन किया गया पाटन मार्जिन याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए पाटन मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन सभी हितरक्षकों से जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों पर आधारित है। जबकि पाटनरोधी याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया गया पाटन मार्जिन उनका पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है।
- (ix) प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई क्षमता से याचिकाकर्ता की प्रभावी क्षमता परिलक्षित नहीं होती है। प्राधिकारी ने पाया है कि याचिकाकर्ता की प्रभावी क्षमता 7500 मी० टन है। इसे जांच की अवधि के लिए न केवल क्षमता उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए बल्कि पिछले वर्षों के लिए भी माना जा सकता है।
- (x) इस तर्क के बारे में कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री प्राप्ति में वृद्धि हुई है अतः कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री कीमत से स्वतः वृद्धि का तात्पर्य कोई क्षति नहीं है क्योंकि बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि के साथ देखी जा सकती है। मौजूदा मामले में उत्पादन की लागत में वृद्धि बिक्री की लागत में वृद्धि से अधिक है। इसका दावा पी आई बी नामतः कोच्ची रिफाइनरी लि० और मै० आई पी सी एल के अन्य विनिर्माताओं द्वारा किया गया है।

## 7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- (क) वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद यूरोपीय संघ, ब्राजील, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और थाइलैण्ड मूल की अथवा वहां से निर्यातित पोलि-आइसो-बुटिलीन हैं जिसे पीआईबी अथवा पोलि-आइसो-बुटालीन (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) भी कहा जाता है। पोलि-आइसो-बुटालीन सी4, ओलिफीन्स स्ट्रीम, जो मुख्यतः आइसोबुटीन का बना हुआ है, के पोलिमराइजेशन से विनिर्मित सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन पालिमेर है। पीआईबी का अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे ल्यूब ऑयल एडीटिव्स केवल फिलिंग कम्पाउण्ड्स, रबड़ मॉडिफायर्स, लेदर कैमिकल्स, 2टी ऑयल फारमूलेशन्स, ऑयलइन्सुलेटर्स एडहेसिव इत्यादि में किया जाता है। वर्तमान जांच में पीआईबी की सभी किस्में शामिल हैं।
- (ख) पीआईबी का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं0 3902.20 के तहत किया गया है।

प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

#### ज. समान वस्तु :

8. पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (घ) में यह उल्लेख है कि "समान वस्तु" का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु से है जो जांच के अधीन उत्पाद से हर प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी किसी अन्य वस्तु से है जिसकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तुओं से काफी मिलती-जुलती हैं।

#### (क) आयातकों और निर्यातकों के विचार:

- (i) सम्बद्ध वस्तु के एक आयातक मै0 इंडियन एडिटिव लि0, चेन्नई ने समान वस्तु के बारे में अनुरोध किया है कि वे एच आर पोलि-आइसो-बुटिलिन (हाइली रीएक्टिव पोलि-आइसो बुटिलिन) का आयात कर रहे हैं। आयातक के अनुसार एच आर पोलि-आइसो-बुटिलिन तथा पोलि-आइसो-बुटिलिन भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। उन्होंने दावा किया है कि इसकी विनिर्माण प्रौद्योगिकी भी भिन्न है और यह किसी भारतीय विनिर्माता के पास उपलब्ध नहीं है।
- (ii) मै0 इंडियन एडिटिव्स लिमि0 ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि चेवरोन ओरोनाइट के साथ प्रौद्योगिकी कथार के तहत उनके ब्रांड नाम (ओ एल ओ ए) (ओरोनाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल एडिटिव) का उपयोग करने के लाइसेंस धारक होने के बावजूद उन्हें ऐसी किसी कच्ची सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं है जो उनके द्वारा अनुमोदित न हो। इस समय ओ एल ओ ए के विनिर्माण के लिए केवल एच आर पी आई बी को स्वीकृति दी गई है और किसी अन्य प्रकार के पी आई बी का उपयोग करने की मनाही है। आयातक ने आगे यह उल्लेख किया है कि जब कोई भारतीय विनिर्माता इस उद्योग में आने का इच्छुक हो तो तब देशी

तौर पर विनिर्मित एच आर पी आई बी का उपयोग करना उनके दीर्घकालीन हित में होगा ।

**(ख) घरेलू उद्योग के विचार:**

- (i) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पोलि-आइसो बुटिलिन और सम्बद्ध देशों से निर्यातित पोलि-आइसो बुटिलिन में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देशों से आयातित पोलि-आइसो-बुटिलिन भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्दिष्टताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में तुलनीय हैं । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं । याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित पोलि-आइसो बुटिलिन पाटनरोधी नियमों के अनुसार सम्बद्ध देशों से आयातित पोलि आइसो-बुटिलिन के समान वस्तु है ।
- (ii) बी ए एस एफ और इंडियन एडिटिक्स लि० के इस दावे के संबंध में कि वे एच आर पी आई बी का निर्यात/आयात करते हैं और यह एक भिन्न उत्पाद है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि निर्यातक/आयातक का ब्यौरा सही नहीं है । एच आर पोलि-आइसो-बुटिलिन कुछ और नहीं बल्कि पोलि-आइसो-बुटिलिन का एक प्रकार है, जोकि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद है (इसी का भारत में आयात किया जा रहा है) । एच आर पोलि-आइसो बुटिलिन और पोलि-आइसो-बुटिलिन समान वस्तु हैं और दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । इन दोनों का भारत में उपभोक्ताओं द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन किया जा रहा है । एक आयातक, इंडियन एडिटिक्स लिमि० घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पी आई बी का उपयोग कर रहा था और अब एच आर पोलि-आइसो-बुटिलिन का उपयोग कर रहा है ।
- (iii) ऐसा समझा जाता है कि इंडियन एडिटिक्स लिमि० एच आर पोलि-आइसो-बुटिलिन का आयात उस आपूर्तिकर्ता के साथ अपने कशर के कारण कर रहा है जिनकी इंडियन एडिटिक्स लि० में पर्याप्त धारिता है, न कि तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से स्थानापन्न किसी मुद्दे के कारण ।
- (iv) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे पोलि-आइसो-बुटिलिन और सम्बद्ध देशों से आयात किए जा रहे पोलि-आइसो-बुटिलिन का भारत में ग्राहकों द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है ।

**9. प्राधिकारी द्वारा जांच:**

प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और सम्बद्ध देशों से आयात किए जा रहे पोलि-आइसो बुटिलीन की भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएं, उत्पाद विनिर्दिष्टताएं, कार्य तथा उपयोग समान हैं । दोनों का उपयोग एक दूसरे

के स्थान पर किया जा रहा है और इस प्रकार ये वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमों के अर्थों के भीतर समान वस्तुएं हैं। एच आर पी आई बी के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एच आर पी आई बी, पी आई बी की एक किस्म है। एच आर पी आई बी का उपयोग कर रही कंपनी पहले पी आई बी का उपयोग कर रही थी। कंपनी ने स्वयं दावा किया है कि वे एच आर पी आई बी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी विदेशी संबद्ध शाखाओं द्वारा किसी अन्य उत्पाद का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस कंपनी का यह तर्क भी नहीं है कि कंपनी तकनीकी रूप से पी आई बी का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा 'समान वस्तु' का उत्पादन किया जाना अपेक्षित है न कि 'मिलती-जुलती वस्तु' का। अतः प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं कि एच आर पी आई बी और पी आई बी समान वस्तुएं हैं।

उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी की धारणा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं।

#### 10. घरेलू उद्योग

पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग का अभिप्राय उन समस्त घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और किसी सम्बद्ध कार्यकलाप में लगे हैं अथवा जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का अधिकांश हिस्सा हो जिनमें ऐसे उत्पादक शामिल नहीं हैं जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से सम्बद्ध हों या उसके स्वयं आयातक हों तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों, को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं समझा जाएगा।" इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन के अनुसरण में तब तक कोई जांच शुरू नहीं करेंगे जहां तक कि वह समान उत्पाद के उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए उक्त आवेदन के समर्थन अथवा विरोध के स्तर की जांच के आधार पर यह निर्धारित न कर लें कि आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है किन्तु उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से कम बनता हो।

#### 11. घरेलू उद्योग के विचार:

घरेलू उद्योग की स्थिति के मुद्दे पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनका पोली-आइसो ब्यूटीलिन के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा, कोच्ची जो संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है (जिसने याचिका का समर्थन भी किया है तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है) आयातकों में से एक (बीपीसीएल) से संबंधित कंपनी है। इसलिए, कोच्ची के उत्पादन को पात्रता संबंधी उत्पादन से बाहर रखा जाना चाहिए। मै0 आई पी सी एल (जो एम पी एल तथा जी पी एल द्वारा उत्पादित पोली-आइसो-ब्यूटीलीन को बेच

रहा है) ने याचिका का समर्थन किया है। अतः याचिकाकर्ता नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति में है।

## 12 आयातकों तथा निर्यातकों के विचार

मै0 डायलिम जो कोरिया से संबद्ध वस्तु के निर्यातक है, ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि बी पी सी एल (भारत पेट्रोलियम निगम लि0) को आबद्ध खपत के लिए घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। तथापि, के आर एल (कोचीन रिफाइनरीज लि0) ने भी अप्रैल 2001 में एच पी सी एल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लि0) से प्राप्त संविदा में सहभागिता की है यद्यपि बी पी सी एल ने वर्ष 2000 में के आर एल को अधिग्रहीत कर लिया है। अतः याचिकाकर्ता जिसका भारत में पोली-आइसो-ब्यूटीलिन के कुल उत्पादन का 25% से कम का हिस्सा है, को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।

## 13. प्राधिकारी द्वारा जांच

यह याचिका मै0 कोठारी सुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि0 मनाली, चेन्नई द्वारा दायर की गई है जिसमें यूरोपीय संघ, ब्राज़ील, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर तथा थाईलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन का आरोप लगाया गया है। जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में 25% से अधिक हिस्सा है। डायलिम का यह तर्क कि याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन में 25% से कम हिस्सा है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अलावा, जांच की शुरुआत के पश्चात् संबद्ध वस्तु के दो भारतीय उत्पादकों जिनके नाम मै0 कोच्ची रिफाइनरीज लि0 और मै0 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि0 (आई पी सी एल) हैं, ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लागू करवाने के लिए याचिका का समर्थन किया है। कोच्ची रिफाइनरीज तथा महाराष्ट्र पोलीब्यूटेन ने अपनी उत्पादन लागत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में माना है कि याचिकाकर्ता नियम 5 (क) एवं (ख) तथा नियम 2 (ख) के तहत यथा उल्लिखित घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने संबंधी अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रकटन विवरण के अपने उत्तर में मै0 भारत पेट्रोलियम निगम लि0 ने यह अनुरोध किया है कि मै0 कोच्ची रिफाइनरीज लि0 द्वारा किये गये निवेदन पूर्व में उनके द्वारा व्यक्तिगत विनिर्माता के रूप में किए जा चुके हैं। 26 मार्च 2001 से मै0 बी पी सी एल ने मै0 के आर एल को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तथापि, प्राधिकारी मानते हैं कि मै0 कोच्ची रिफाइनरीज लि0 एक अलग वैधानिक इकाई और जांच की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय उन्होंने याचिका से अपना समर्थन स्पष्ट रूप से वापस नहीं लिया है।

प्रारंभिक जांच परिणामों के पश्चात्, मै0 महाराष्ट्र पोलीब्यूटेन ने भी आई पी सी एल के जरिए अपना उत्पादन लागत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी पाते हैं कि एम पी एल द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई उत्पादन

लागत से अधिक है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिकाकर्ता याचिका दायर करने संबंधी मापदण्डों को पूरा करते हैं। प्राधिकारी नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी को घरेलू उद्योग भी मानते हैं।

**ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन**

**14.** धारा 9 क (1) (ग) के अधीन किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हों, या
- (ii) जब निर्यात देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की समुचित तुलना नहीं हो सकती हो, तो सामान्य मूल्य या तो :

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य : या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित, प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत :

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो, तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण, मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

प्राधिकारी ने उपरोक्त धारा के अनुसार संबद्ध देश के निर्यातकों को जांच से संबद्ध सूचना तथा टिप्पणियां, यदि कोई हो, देने का अवसर प्रदान किया। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/उच्चायोगों को भी पत्र लिखे।

**15. यूरोपीय संघ का क्षेत्र**

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के क्षेत्र के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली में सूचना नहीं दी तथापि, मै0 बायर, जर्मनी ने टिप्पणियां दी हैं जिन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों में ध्यान में रखा गया है।

प्रारंभिक जांच-परिणामों में सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई पोली-आइसो-ब्यूटीलीन की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इसे ही स्वीकार किया है। तदनुसार, यूरोपीय संघ क्षेत्र के सभी निर्यातकों के लिए पोली-आइसोब्यूटीलीन का सामान्य मूल्य xxxxxx यू एस डालर प्रति मी0 टन माना गया है।

(ख) निर्यात कीमत:

यूरोपीय संघ क्षेत्र से किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता के आंकड़े पर आधारित निर्यात कीमत को स्वीकार किया था। समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और कमीशन को याचिकाकर्ता के दावों के आधार पर क्रमशः xxx, xxx, xxx, xxx तथा xxx डालर/मी0 टन की सीमा तक माना गया है। इस प्रकार जांच अवधि में निर्यात कीमत xxx डालर/मी0 टन परिकलित होगी।

**16. ब्राजील**

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्राजील के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना नहीं दी है।

जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के समय सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा दिये गए पोली-आइसो-ब्यूटीलीन की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इसे ही अपनाते हैं। तदनुसार, ब्राजील के सभी निर्यातकों के लिए पोली-आइसो-ब्यूटीलीन का सामान्य मूल्य xxx यू एस डालर प्रति मी0 टन माना गया है।

(ख) निर्यात मूल्य

ब्राजील के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में निर्यात कीमत को डी जी सी आई

एण्ड एस, कलकत्ता के आंकड़ों के आधार पर स्वीकार किया था। समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और कमीशन को याचिकाकर्ता के दावों के आधार पर क्रमशः XXXX, XXX, XXX, XXX, तथा XXX डालर/मी० टन की सीमा तक माना गया है। इस प्रकार जांच अवधि के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत XXX डालर/मी० टन बनती है।

## 17. जापान

### (क) सामान्य मूल्य:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना नहीं दी है।

प्रारंभिक जांच परिणामों में सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा दी गई पोली-आइसो-ब्यूटीलीन की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इसे ही स्वीकार करते हैं। तदनुसार, जापान के सभी निर्यातकों के लिए पोली-आइसो-ब्यूटीलीन का सामान्य मूल्य XXX यू एस डालर प्रति मी० टन माना गया है।

### (ख) निर्यात कीमत

जापान के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हैं। याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर प्राधिकारी ने संतुलित औरत निर्यात कीमत का निर्धारण जापान के निर्यातकों द्वारा मै० इंडियन ऑयल कारपोरेशन के लिए प्रस्तावित कीमतों और जांच अवधि के लिए डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता के निर्यात आंकड़ों के आधार पर किया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार तथा कमीशन क्रमशः XXX, XXX, XXX, XXX तथा XXX की सीमा तक स्वीकार किया है। जांच अवधि में कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत XXX डालर/मी० टन बनती है।

## 18. कोरिया आर.पी

### मै० डायलिम कारपोरेशन, सियोल, कोरिया

(क) प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया आर पी के केवल एक निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के आधार पर अपेक्षित सूचना दी है। मै० डायलिम ने जांच अवधि के दौरान कोरिया आर पी में संबद्ध वस्तु की बिक्रियों संबंधी बीजक-वार ब्यौरे उपलब्ध कराये हैं। निर्यातकों द्वारा दावा किए गए उत्पादन लागत संबंधी ब्यौरों के आधार पर, घरेलू बाजार में

बिक्रियां उत्पादन लागत से अधिक हैं और इसलिए इन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में माना गया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात/उत्पादक द्वारा उल्लिखित समायोजनों को माना था। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इसे ही माना है। जांच अवधि में संतुलित औसत कारखाना से बाहर आने पर घरेलू बिक्री कीमत XXX यू एस डालर/मी० टन परिकलित हुई है।

(ख) निर्यात कीमत:

चूंकि कोरिया आर पी के किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के आंकलन के लिए अन्य सहयोगी निर्यातक द्वारा इंगित संतुलित औसत घरेलू बिक्री कीमत को स्वीकार किया था। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इसे ही माना है।

- (ख) प्राधिकारी ने कोरिया आर पी के सहयोगी निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई भारत के लिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, वीमा, कमीशन आदि पर बिना किसी समायोजन के स्वीकार किया है। जांच अवधि के लिए कारखाना से बाहर आने पर निर्यात कीमत XXX यूएसडालर/मी० टन परिकलित हुई है।

20. सिंगापुर

(क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगापुर के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना नहीं दी है।

जांच परिणामों में सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा दी गई पोल-आइसो-ब्यूटीलीन की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इन्हें ही स्वीकार किया है। तदनुसार, सिंगापुर के सभी निर्यातकों के लिए पोल-आइसो-ब्यूटीलीन का सामान्य मूल्य XXX यू एस डालर प्रति मी० टन माना गया है।

(ख) निर्यात मूल्य

सिंगापुर के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात कीमत संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता के दावों के आधार पर प्राधिकारी ने भारत औसत निर्यात कीमत का निर्धारण सिंगापुर के निर्यातकों द्वारा मै० इंडियन ऑयल कारपोरेशन को प्रस्तावित कीमतों तथा जांच अवधि के लिए डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता के निर्यात

आंकड़ों के आधार पर किया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और कमीशन को क्रमशः XXX, XXX, XXX, XXX, तथा XXX यू एस ए डालर/मी० टन की सीमा तक माना है। इस प्रकार जांच अवधि में कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत XXX डालर/मी० टन बनती है।

## 21. थाईलैंड

### (क) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार सूचना नहीं दी है।

जांच परिणामों में सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता द्वारा दी गई पोल-आइसो-ब्यूटीलीन की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों के लिए भी इन्हें ही स्वीकार किया है। तदनुसार, सिंगापुर के सभी निर्यातकों के लिए पोल-आइसो-ब्यूटीलीन का सामान्य मूल्य XXX यू एस डालर प्रति मी० टन माना गया है।

### (ख) निर्यात मूल्य

थाईलैंड के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली के जवाब में निर्यात कीमत संबंधी ब्यौरे नहीं दिये हैं। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत को स्वीकार किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अन्तर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार तथा कमीशन को याचिकाकर्ता के दावों के आधार पर क्रमशः XXX, XXX, XXX, XXX तथा XXX डालर/मी० टन की सीमा तक माना गया है। इस प्रकार जांच अवधि के दौरान कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत XXXX डालर/मी० टन परिकलित होती है।

## अ. पाटन-सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत में तुलना

### 22. तुलना संबंधी नियम निम्नानुसार हैं:-

- (क) 'पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यतः कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथा संभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी।
- (ख) जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी: अंतर में शामिल हैं बिक्री की शर्तें, कराधान, व्यापार के स्तर,

मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य अंतर जो कीमत की तुलना को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं।"

- (ग) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को विनियमित करने वाले सिद्धांतों को अपनाने की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 में यथा निर्धारित संगत नीति का अनुसरण किया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के मामले में पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है जो निम्न तालिका में दिया है:-

देशवार निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य(डालर/मी० टन)	निर्यात कीमत (डालर/मी० टन)	पाटन मार्जिन (%)
<b>कोरिया आर.पी</b>			
(i) मै० डायलिम कारपोरेशन लि०	XXXX	XXXX	15.72%
(ii) अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	XXXX	XXXX	46.29%
<b>सभी निर्यातक/उत्पादक</b>			
(i) यूरोपीय संघ क्षेत्र	XXXX	XXXX	18.03%
(ii) ब्राजील	XXXX	XXXX	44.63%
(iii) जापान	XXXX	XXXX	57.23%
(iv) थाइलैंड	XXXX	XXXX	19.09%
(v) सिंगापुर	XXXX	XXXX	34.36%

उपरोक्त पाटन-मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

#### य. क्षति एवं कारणात्मक संबंध :

23. पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 निम्नानुसार है :-

##### 'क्षति का निर्धारण'

- (i) विनिर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे की जांच परिणाम को रिकॉर्ड करेंगे कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से किसी स्थापित उद्योग को क्षति अथवा महत्वपूर्ण क्षति की आशंका उत्पन्न होती है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से करती है।

- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति की आशंका, घरेलू उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण बाधा तथा पाटित आयात एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण सभी संगत साक्ष्यों अर्थात् लाइम वस्तुओं के घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत इन नियमों के अनुबंध-II में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार करेंगे ।

24. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II में निर्दिष्ट क्षति के निर्धारण हेतु सिद्धांतों में निम्नलिखित व्यवस्था है :

- (i) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु की घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होंगे ।
- (ii) पाटित आयातों की मात्रा की जांच के समय, कथित प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के अनुरूप महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । नियम 19 के उप-नियम (2) में यथानिर्दिष्ट कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत को उस स्तर तक दमन करने अथवा रोकने का है जो कि अन्यथा काफी अत्यधिक बढ़ गई होती ।
- (iii) भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच हेतु, उद्योग की स्थिति जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा तथा मार्जिन इत्यादि से संबंधित सूचकों पर उपरोक्त नियम के अनुबंध 11 (iv) के अनुसार विचार किया गया है ।

#### ट. क्षति का संचयी मूल्यांकन

- 25 (क) उपरोक्त नियम 11 के अधीन अनुबंध 11 (iii) में व्यवस्था है कि 'ऐसे मामले में जहां किसी उत्पाद का आयात पाटनरोधी जांच के अधीन एक से अधिक देशों के साथ-साथ किया जा रहा है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी आधार पर तभी करेंगे जब कि वे निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है तथा प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देश का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक परिकलित होता है तथा आयातों का संचयी निर्धारण आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उचित है ।

- (ख) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन तथा संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा उन पर निर्धारित सीमा से अधिक है। यूरोपीय संघ क्षेत्र, ब्राजील, जापान, कोरिया आर पी, सिंगापुर तथा थाइलैंड से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि इन देशों से निर्यात कीमतें भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमतों से सीधे ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे तथा यहां घरेलू उत्पादकों को विस्थापित कर रहे थे।

26. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले ऊपर निर्दिष्ट सभी आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा इत्यादि की निम्नानुसार जांच की गई है :

(क) आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्सा

पोलि-आइसो-ब्यूटिलिन के आयातों की मात्रा के संबंध में सूचना डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सूचना पर आधारित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का बाजार हिस्सा 1999-2000 के दौरान संचयी रूप से 73.60% था। जोकि जांच अवधि के दौरान बढ़कर 86.62% हो गया है। 1999-00 की तुलना में जांच अवधि के दौरान कुल आयात में करीब 13% की वृद्धि हुई है।

(ख) उत्पादन

वर्ष 1999-00 के दौरान संबद्ध वस्तुओं के याचिकाकर्ता कम्पनी का कुल उत्पादन 6111 मी० टन से घटकर जांच अवधि के दौरान करीब 7.58% की कमी प्रदर्शित करते हुए 5648 एम टी (वार्षिक आधार पर) हो गया।

(ग) बिक्रियों की मात्रा

वर्ष 1999-00 के दौरान याचिकाकर्ता कम्पनी की बिक्रियों की मात्रा 6392 मी० टन थी, जोकि जांच अवधि के दौरान करीब 18.38% की कमी प्रदर्शित करते हुए घटकर 5217 मी० टन (वार्षिक आधार पर) रह गयी।

(घ) क्षमता उपयोग

याचिकाकर्ता ने वर्ष 1999-00 में 81.48% की औसत क्षमता उपयोग हासिल किया जोकि पीओआई के दौरान घटकर 75.31% हो गया।

(ङ.) बिक्री प्राप्ति

वर्ष 1999-00 के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से याचिकाकर्ता कम्पनियों की औसत बिक्री प्राप्ति रु० XXX प्रति मी० टन थी, जोकि 2000-01 में 5.26% की

वृद्धि दिखाते हुए बढ़कर ₹0 XXX प्रति मी० टन हो गया । तथापि, जांच अवधि के अंतिम पांच महीनों के दौरान औसत बिक्री प्राप्ति घटकर XXX हो गयी । यह स्वयं जांच अवधि में घरेलू बिक्री-प्राप्ति में अत्यधिक कमी प्रदर्शित करता है । तथापि, यह स्थापित किया गया है कि 1999-00 की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की औसत उत्पादन लागत बढ़कर ₹0 XXX प्रति मी० टन हो गया है । तदनुसार, जांच अवधि के दौरान बिक्री प्राप्ति में वृद्धि ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति नहीं की है ।

(च) लाभप्रदत्ता

यह अवलोकन किया गया है कि याचिकाकर्ता 1999-00 के दौरान संबद्ध वस्तु के प्रति मी० टन ₹0 XXX का निवल लाभ कमा रहा था । तथापि, जांच अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तुओं से याचिकाकर्ता को ₹0 XXX प्रति मी० टन का घाटा हुआ ।

(छ) प्राप्त न हुए ठेके का साक्ष्य

मै० इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जारी की गई संविदा में निर्यातकों द्वारा अत्यधिक न्यूनतम कीमत उद्धृत किए जाने के कारण घरेलू उद्योग संविदा प्राप्त नहीं होगी। तो भी एकमात्र संविदा जिसमें याचिकाकर्ता ने सबसे कम कीमत दिखाई है, के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी घाटा उठाना पड़ेगा ।

(ज) अंतिम स्टॉक

वर्ष 1999-2000 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का अंतिम स्टॉक 35.1% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए XXX मी० टन से बढ़कर XXX मी० टन हो गया है ।

(झ) नकदी प्रवाह

पीआईबी के विनिर्माण कार्य-कलापों द्वारा घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में हुई वृद्धि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के समान है । घरेलू उद्योग का नकदी प्रवाह मुनाफों में कमी के कारण गंभीर रूप से कम हुआ है ।

(य.) निवेशों पर लाभ

पीआईबी के संबंध में घरेलू उद्योग के निवल लाभ और निवेश संबंधी लाभ के बीच नकारात्मक रूख है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए प्रति किलोग्राम पर घाटा उठाया गया है ।

(ट) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

आयातित सामग्रियों का पहुंच मूल्य उत्पादन लागत से काफी कम है तथा घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से भारतीय बाजार में कीमत में कमी तथा ह्रास हो रहा है।

(ठ) पाटन मार्जिन की मात्रा

संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन मात्र न्यूनतम सीमा से अधिक ही नहीं है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसलिए, घरेलू उद्योग पर पाटन मार्जिन का पर्याप्त प्रभाव है।

(ड) वृद्धि

जबकि घरेलू उद्योग पीआईबी का उत्पादन तथा बिक्री उस कीमत पर कर रहे हैं, जिस पर घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद बेचने को बाध्य किया गया है, अलाभकारी कीमतें हैं तथा घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बेचे गए पीआईबी के प्रति किग्रा. पर हानि उठा रहा है। इसलिए, सभी याचिकाकर्ता कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के संबंध में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करती हैं।

(ढ) वेतन

घरेलू उद्योग के प्रति कर्मचारी का वेतन जोकि बढ़ रहे थे, जांच अवधि में कम हो गए जिसके कारण कर्मचारी अपने भविष्य के बारे में चिंतित हुए तथा कर्मचारी नये रोजगार की तलाश में हैं।

(ण) रोजगार

घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर स्थिर है, तथापि घरेलू उद्योग के घाटों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों में उनके भविष्य के संबंध में बुरा प्रभाव पड़ा है तथा कर्मचारी नये रोजगार की तलाश में हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तव में क्षति हुई है।

त. कारणात्मक संबंध

27(क) प्रारंभिक जांच परिणामों में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा संबद्ध देशों से निर्यातों के पहुंच मूल्य की सावधानी पूर्वक जांच करने के पश्चात प्राधिकारी ने नोट किया है कि यूरोपीय संघ क्षेत्र(ई.यू) तथा थाइलैंड के मामले में जांच अवधि के दौरान निर्यातों का औसत पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित क्षति रहित कीमत से अधिक था। तदनुसार, इन देशों

से निर्यातों तथा घरेलू उद्योग को हुई पर्याप्त क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने नोट किया कि बाकी देशों नामतः ब्राजील, जापान, कोरिया आर.पी. तथा सिंगापुर से पोलि-आइसो-ब्यूटीलिन का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है। प्राधिकारी इस संबंध में अपने जांच परिणामों की अंतिम जांच-परिणाम में भी पुष्टि करते हैं।

- (ख) प्राधिकारी पाते हैं कि डीजीसीआईएंड एस द्वारा सूचित तथा इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जारी निविदा में यथा उद्धृत संबद्ध देशों से अमरीकी डालर के अनुसार अधिमानित औसत निर्यात कीमत में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। याचिकाकर्ता कम्पनी का उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में कमी के कारण क्षति हुई। याचिकाकर्ता कम्पनी संबद्ध वस्तुओं की लाभ पर बिक्री कर रहे थे तथा उन्हीं वस्तुओं को जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में पर्याप्त घाटों पर बेच सकते थे। बिक्री कीमत में कमी के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा बिक्री मात्रा में कमी आई। यह सारे मापदंड संचयी रूप से इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता कम्पनी को वास्तविक क्षति हुई है तथा याचिकाकर्ता कम्पनियों को संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।

#### थ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे:

- 28(क) सामान्यतया, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन को खत्म करना है, जोकि याचिकाकर्ता कम्पनी को क्षति पहुंचा रहा है तथा भारतीय बाजार में एक मुक्त तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करना, जोकि देश के सामान्य हित में है।

- (ख) प्राधिकारी पाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का आरोपण संबद्ध वस्तुओं के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कम नहीं किया जाएगा, खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क को किसी आवश्यक राशि तक याचिकाकर्ता कम्पनी की क्षति को सुधारने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन कार्य-कलापों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभों को समाप्त किया जाएगा, याचिकाकर्ता कम्पनियों को ह्रास से रोका जाएगा तथा पोलि-आइसो-ब्यूटीलिन उपभोक्ताओं के विविध पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी, पाटनरोधी उपायों के लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए, उपभोक्ताओं हेतु उत्पाद की अनुपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

#### द. निष्कर्ष

29. उपरोक्त पर विचार करने पर यह देखा जाता है कि:-

- (क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलि-आइसो-ब्यूटीलिन का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके कारण पाटन हुआ है।
- (ख) भारतीय उद्योग को कीमत कटौती, कीमत में मंदी तथा ब्राजील, जापान, कोरिया आर.पी. तथा सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- (ग) ब्राजील, जापान, कोरिया आर.पी. तथा सिंगापुर से पाटित आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है।
30. ब्राजील, जापान, कोरिया आर.पी. तथा सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलि-आइसो-ब्यूटीलिन के सभी आयातों पर एक निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझा गया है।
31. इस बात पर विचार किया गया था कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। इस प्रयोजनार्थ, आयातों का औसत पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि हेतु निर्धारित याचिकाकर्ता कम्पनी की क्षति रहित कीमत से की गई थी। जहां कहीं भी अंतर पाटन मार्जिन से कम था, पाटन मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की गई है। तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 अथवा किसी अन्य अध्याय के अंतर्गत ब्राजील, जापान, कोरिया आर.पी. तथा सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेड की संबद्ध वस्तुओं पर नीचे कालम (2) में इंगित राशि तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

देशवार निर्यातक/उत्पादक	राशि प्रति एम टी अमरीकी डालर में
<u>कोरिया आर.पी.</u>	
(i) मै0 डायलिम कारपोरेशन लि0	1037.77
(ii) अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	1037.77
<u>निम्नलिखित देशों के भी निर्यातक/उत्पादक</u>	
(i) यूरोपीय संघ क्षेत्र	लागू नहीं होता
(ii) ब्राजील	1037.77
(iii) जापान	1037.77
(iv) थाइलैंड	लागू नहीं होता
(v) सिंगापुर	1037.77

32. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुँच मूल्य का निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्कों सहित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमा शुल्क विभाग द्वारा यथाअकलित मूल्य के अनुसार किया जाएगा ।
33. उपरोक्त के अध्यक्षीन, प्राधिकारी दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 के प्रारम्भिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।
34. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तश्रृषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2002

### FINAL FINDINGS

**Subject : Anti-Dumping Investigations concerning imports of Poly-Iso-Butylene originating in or exported from European Union, Brazil, Japan, Korea R. P., Singapore and Thailand.**

No. 47/1/2001-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

### A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:
  - (i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification No 47/1/2001-DGAD dated the 12<sup>th</sup> December, 2001 with regard to Anti Dumping investigations concerning imports of Poly-Iso-Butylene from European Union, Brazil, Japan, Korea R.P., Singapore and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication:
  - (ii) The Authority forwarded a copy of the Preliminary Findings to known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter;
  - (iii) The Authority also forwarded a copy of the Preliminary Findings to the Embassies of subject countries in New Delhi with a request to furnish their views on the Preliminary Findings:
  - (iv) The Authority held a public hearing on 28<sup>th</sup> February, 2002 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, importers and exporters. The parties attending the

public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions thus received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;

- (v) The Authority made the public file available to all interested parties containing non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties, for inspection, upon request;
- (vi) Arguments raised by interested parties before announcing of Preliminary Findings, which have been brought out in the Preliminary Findings notified earlier have not been repeated herein for sake of brevity. However, arguments raised by the interested parties have been appropriately dealt with in the Preliminary Findings and/or these findings;
- (vii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (viii) Investigation was carried out for the period starting from 1<sup>st</sup> April, 2000 to 31<sup>st</sup> August, 2001;
- (ix) \*\*\*\* in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.

**B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY:**

**2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY:**

**(i) ON DUMPING:**

Only two exporters/producers responded to the Designated Authority. Exporter from European Union, BASF, has merely advanced arguments. No factual information in the form and manner prescribed has been filed by the exporter. None of the other exporters except Daelim from Korea has responded to the Designated Authority. The Domestic Industry has supported the determination of dumping and dumping margin by the Designated Authority done in the preliminary findings and requested the Designated Authority to confirm the preliminary findings in this regard. Other responding exporter from Korea RP i.e. M/s. Daelim has not filed any Non-Confidential summary of the response. Hence, they are unable to comment over

the response filed by the exporter and claims made by the company. However the Domestic Industry has submitted that it is found from the preliminary findings that the exporter itself has accepted that there was significant dumping margin in respect of exports made by the company. The comments filed by the company clearly points towards dumping prices at which the material has been exported by the company. It is relevant to point out in this regard that comparison of export price to India with export price to other countries is of no relevance when the exporter has viable domestic sales.

The Domestic Industry further requested that in case of dumping from EU, none of the exporter have cooperated. Substantial imports from France alone are entering the country at very low price which is below the Non Injurious Price. In line with the practice of the Designated Authority where an exporter has cooperated the Authority has determined dumping margin and / or injury margin in case of other non cooperative exporter on the basis of lowest export price of the cooperative exporter. In the instant case when non of the exporters has cooperated with the Designated Authority, the dumping margin and/or injury margin be determined on the basis of these low priced imports rather than weighted average export price

(ii) **ON INJURY:**

- (a) The information with regard to various parameters relating to the Domestic Industry clearly establish that the Domestic Industry has suffered material injury
- (b) The injury to the Domestic Industry is required to be examined cumulatively from all sources dumping the material in India, as the criteria laid down in Annexure II to the Rules is fully satisfied.
- (c) The imports from the subject countries have increased in absolute terms as well as in relation of production and consumption of Poly-Iso-Butylene in India.
- (d) Market share of imports from subject countries in total imports as well as demand of Poly-Iso-Butylene in India has increased.
- (e) With use of Poly-Iso-Butylene being made mandatory in 2 stroke engine oils, demand of Poly-Iso-Butylene increased significantly. However, the exporters from the subject countries increased their dumping practices
- (f) Till 1999-00, production and sales of the domestic industry increased due to increase in demand. However, in 2000-2001 as also rest part of Period of Investigation, production of the Domestic industry declined

significantly due to decline in sales. In fact, significant decline in sales forced the Domestic Industry to curtail the production.

- (g) The Landed Price of imports from subject countries were much below the selling prices or and Non Injurious Price, resulting in consumers switching over to imported products. The Domestic Industry was not able to sell its product, resulting in significant increase in stocks with the company. While the storage facilities with the Domestic Industry was full and the company was forced to resort to outside storage of material, the company had to resort to cut in production to tide over the difficulty of storing the material
- (h) The cost of production of the Domestic Industry increased, whereas, the Domestic Industry was not able to increase its selling price proportionately. Thus, the imports prevented the Domestic Industry from effecting legitimate price increase
- (i) The imports were causing severe price suppression/depression in the Indian market.
- (j) The Domestic Industry was forced to face severe financial losses, as the selling prices were inadequate to recover the cost of production.
- (k) The return on investment were negative for the Domestic Industry
- (l) The Domestic Industry faced severe cash flow problems.
- (m) The petitioner has concluded that Domestic Industry suffered material injury from the dumped imports. Further, the imports were causing threat of further material injury, as the exporters are holding huge capacities, the price undercutting was severe (as is evident from the prices offered to IOC in the open tender) and rate of increase of imports was rather significant and steep.

(iii) **OTHER ISSUES**

- a. While the interim duty is already in US\$, the final duties may also be recommended in terms of US\$ only, so that erosion in the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate
- b. The reference price determined by the Designated Authority do not provide due relief to the Domestic Industry and the reference price should be reviewed and revised upward.
- c. No duties have been recommended in case of imports from EU and Thailand in the preliminary findings. The petitioner has submitted that the export price from these countries were at injurious level.

Accordingly, they have requested the Designated Authority to apply the practice of determination of export price in case of non cooperative exporters in case of these two countries, which would establish that the imports from these countries were also at injurious levels.

- d. The submissions made by Lubrizol can not be considered as submissions made by Oil Companies. There is neither any authorization by other companies nor other companies have signed the representation filed by Lubrizol. Lubrizol is not even an Oil Company. Thus, entire submissions made by Lubrizol under the cover of Oil Company are with misrepresentation of facts
- e. None of the interested parties who have filed these submissions have filed questionnaire response. It is clearly abuse of liberty granted to an interested party to participate in such an investigation, wherein the interested party does not file factual information and rather resorts to mere statements.
- f. Inability of the petitioner or domestic industry to meet full demand of the product in the Country is not a prerequisite to seek Anti Dumping Duty on unfairly priced dumped imports. Hon'ble CEGAT has upheld this view in a number of investigations. In the appeal relating to EPDM Rubber, the Hon'ble Tribunal held that in case domestic industry is not in a position to meet the requirement i.e. demand, it does not mean that the material should be permitted to be dumped in the Indian market.
- g. The Indian industry can meet present actual demand of PIB in India and is in a position to meet increased demand also with further debottlenecking. The Indian industry is at present producing more than 2000 MT per month, which is sufficient to meet entire actual demand of PIB in India.
- h. The Indian Capacity of PIB was much more than demand in India. Effective April 1998, Government of India made use of Poly Iso Butylene in all 2-stroke engine oils mandatory, which resulted in sudden spurt in demand of Poly Iso Butylene in India. Considering the same, even before the Indian Producers could gear them up for the increased demand of the consumers, the foreign producers who were already holding high capacities found it quite lucrative to sell huge volumes in the Indian market. While such exports are not to be condemned, the same can not be allowed at dumping prices, particularly when this causes injury to the domestic industry
- i. The argument that the landed price of imports from Singapore is higher than non-injurious price (and, therefore, there is no injury from Singapore) is factually incorrect. The information provided to the

Designated Authority shows that the landed price of the material being exported from Singapore is lower than NIP of the domestic industry.

- j. These interested parties have very conveniently ignored the Open Tender floated by IOCL. The exporters and producers from some of the subject countries had quoted prices in the global tenders floated by Indian Oil Corporation. Separate prices were quoted for the deliveries to be made at Trombay, Chennai and Calcutta. The prices quoted in the tender no COM/GT/IF/Lube dated 27<sup>th</sup> April, 2001 for procurement of 5200 MT subject product opened on 19<sup>th</sup> July, 2001 clearly shows that the prices quoted by these exporters were significantly below the prices offered by the domestic industry and their selling price.
- k. The statement of the opposing interested parties is contrary to their own statements at various places made in their submissions. It has been stated that the Indian industry can not meet demand of PIB, therefore, they have no option but to import even at higher prices. Should there be shortage of the product in the Country, the domestic industry would not have been forced to hold very high level of stocks and still lower the capacity utilization of the plant. Nor would have the domestic industry charged lower than the price of the imported product, as alleged by these interested parties.
- l. Arguments of the interested parties that the domestic industry was selling below the landed price of imports is not correct as most of the consumers are in Public Sector, who are obliged to procure their material on the basis of lowest price quotation. Further, these companies took price quotations from the Indian Producers also. Such being the case, it is unbelievable that these companies placed orders at prices, which were higher than lowest price. Naturally, these companies found the landed price of imports lower than the prices offered by the domestic industry.
- m. The opposing interested parties have referred to a decision of WTO Dispute Settlement Body regarding injury parameters. The Petitioner has drawn attention to para (iv) of Annexure II of Indian Anti-Dumping Rules. The Designated Authority is required to look towards decisive factors, which would guide Designated Authority in giving a finding of injury. The Designated Authority is required to evaluate only all relevant parameters. Those parameters which are not relevant or which does not show injury in the opinion of the domestic industry are not required to be brought out in the findings. The petitioner has also referred to Rule 12 (and 17) of the Rules, which states that the Designated Authority is required to record relevant consideration for injury determination and main reasons leading to determination. With regard to decision of Dispute Settlement Body of WTO, the petitioner has submitted that the Designated Authority is conducting investigations in

accordance with Indian Anti Dumping Rules. The decision of the WTO Dispute Settlement Body is not binding on the Designated Authority.

- n. Argument is raised by the opposing interested parties that the petitioner capacity is 5500 MT per annum (as given in their Balance Sheet) and not 7500 MT as mentioned in the petition. It is submitted in this connection that a technical audit of petitioner plant was earlier done by M/s. Kvaerner Powergas India Pvt. Limited, According to the technical audit report, petitioner can produce 7500 MT PIB. Hence capacity has been taken as 7500 MT in the petition. It is also relevant to point out that against a capacity of 7500 MT, the petitioner actually achieved a best production of 6111 MT in the year 1999-00.
- o. Selling price is one of the parameters relevant to injury to the domestic industry. Mere increase in selling price does not mean "any injury". The increase in selling price has to be seen alongwith the increase in the cost of production. In the instant case, cost of production of the domestic industry increased more than increase in selling prices as is also evident from the table below:-

Rs. Pmt	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
Cost of production	100	107.50	129.04	122.29
Selling Price	100	116.31	123.50	113.90
Profit/Loss	100	386.67	-46.51	-143.88

Note: Indexed figures

It is evident from the above that the domestic industry was prevented from effecting legitimate price increases by the dumped imports.

- p. Reference to the BIFR is irrelevant and out of context. A BIFR Company does not mean that the company is closed or unviable. It is also relevant to point out that the company is not BIFR due to its Poly Iso Butylene operations. The company is BIFR due to other products of the company. The Company continues to produce and sell Poly Iso Butylene efficiently in the domestic market. The market is, however, now threatened by the exporters from the subject countries.

C. **VIEWS OF IMPORTERS, EXPORTERS & OTHER INTERESTED PARTIES**

3. **M/S. MOHINI ORGANICS PVT. LIMITED:**

M/s. Mohini Organics Pvt Limited, one of the small scale unit using PIB as a raw material, has submitted that:-

- (a) Anti Dumping Duty levied on the PIB be withdrawn forthwith in view of the price competitiveness and to make them more competitive for the finished product. Since there is no Anti Dumping Duty on the final products manufactured from PIB hence there is more

possibility of the import of final product where the PIB is one of the inputs. Thus the Indian Manufacturers of these final products will be out in the competition.

- (b) The manufacturers of the PIB under PSU's be instructed to supply the material to SSI sector at the same price at what they are supplying to the other PSU's of bulk customers.
- (c) The manufacturers of PIB under PSU's be instructed to maintain the continuity and ensure the regular supplies to the SSI unit for their requirements.

**D. JOINT REPRESENTATION BY OIL INDUSTRY MEMBERS:**

4. Following members of Oil Industry have represented that the Anti Dumping Duty on Poly-Iso-Butylene should not be recommended :

1. Indian Oil Corporation Ltd., Mumbai,
2. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai,
3. Bharat Petroleum Corporation Ltd., Mumbai,
4. IBP Company Ltd., Calcutta,
5. Castrol India Ltd., Mumbai
6. Lubrizol India Pvt., Ltd., Mumbai.

Arguments raised in the representation are discussed as under:-

- (i) As against a total Indian demand of about 35000 MTPA, the Domestic Industry could supply only between 18800 MTPA(at 90% capacity utilisation ) to 24000 MTPA( at 115% capacity). There will be a short fall of a minimum of 11000 MTPA which may go up to 14120 MTPA depending upon the capacity utilisation of the Domestic Industry.
- (ii) The average CIF price of exports from Singapore was Rs.36.45 per Kg which is higher than the average CIF price of Rs.35.33 per Kg. from Thailand. Since the CIF price is higher, landed value of exports from Singapore could not have been lower than that of Thailand therefore anti dumping duty imposed against imports from Singapore may be withdrawn immediately.
- (iii) It appears that the Authority had calculated the export price for Singapore based on DGCIS statistics plus the price quoted to IOCL in a tender. According to our information, there were two tenders floated by IOCL. The first tender was opened on 22.3.2000 and the order was placed during the investigation period. In this tender, the price from Singapore was much higher and Singapore did not get any

order at all. Hence, there was no export price at all under this tender as no sales were at all effected. The next tender was opened on 8.6.2001 but the order was placed in Oct., 2001 much after the Period of Investigation. In any case, in this tender the Domestic Industry obtained the order and Singapore was not even figuring in the list. Hence the export price for Singapore should be based only on DGCIS statistics and at that price, the landed value is higher than the Non-Injurious Price.

- (iv) In an injury analysis, Designated Authority is required to evaluate all the 15 factors specified in Paragraph (iv) of Annexure II to the anti dumping rules. However, in this case, the authority has evaluated only 8 of the 15 mandatory factors. In the Cotton-Type Bed Linen case Government of India argued before the WTO Dispute Settlement Body that all the 15 factors are mandatory and should be evaluated by the European Commission in an anti dumping investigations. WTO Dispute Settlement Body agreed with the argument and decided the case accordingly. It is surprising that Government of India has not followed what it has itself championed for Preliminary Findings is defective as the authority has not evaluated all the 15 factors
- (v) According to the Preliminary Findings sales realization during the Period of Investigation has increased. Therefore, the domestic sales price have not fallen during the Period of Investigation indicating absence of price effect.
- (vi) Comparing the closing stock at the end of two periods is not a correct evaluation of this factor. The evaluation is not proper. The decision of the authority that the domestic industry has suffered injury on this factor is wrong as the Authority has not looked at the average inventory holding through out the year
- (vii) In terms of paragraph 5 of Annexure II of Anti dumping Rules, the Designated Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry. The rules provide that injury caused by such factors must not be attributed to the dumped imports. Therefore, the authority should have taken into account the effect of these factors while evaluating the injury. The authority should have made the required adjustments in respect of each of the above factors while determining the Non-Injurious Price of the Domestic Industry.

- (viii) There is a wide variation between the cost structures of the petitioner company and other domestic producers of PIB in India. The inability of the petitioner to operate as efficient as other domestic producers is one of the major causes of their injury and such inefficiency cannot be attributed to the increased imports.
- (ix) The petitioner company is a BIFR company. The costs of such a sick company cannot be representative of the domestic producers in India, who are non-BIFR companies.
- (x) The reference price should be fixed at the CIF level. If the reference price is fixed on landed value basis, and the anti dumping duty is levied as the difference between this reference price and the actual landed value of goods, the changes in customs duty rates occurring after the period of investigation are not considered.
- (xi) There is no injury either to the Petitioner or to the Domestic Industry as the local manufacturers were operating at 100% capacity utilisation during the period of investigation and even prior to the investigating period.
- (xii) The market share of imports will depend upon the availability of right quality and quantity of Poly-Iso-Butylene from local manufacturers. Due to inability of the petitioner to appropriately source its raw material supply, there are several occasions, when the petitioner as well as other domestic manufacturers had conveyed their inability to supply the desired quantity of Poly-Iso-Butylene.
- (xiii) The petitioner has brought in irrelevant issue about the dumping practices whereas the domestic manufacturers of Poly-Iso-Butylene are not in a position to fulfill country's demand. Just because there is import of Poly-Iso-Butylene and that too, to fulfill the gap between demand and supply, it is incorrect on the part of the Petitioner to state that the exporters have increased their dumping practices.
- (xiv) The Petitioner has incorrectly stated that there is a decline in sales and hence, the Domestic Industry is forced to curtail production. The petitioner has produced 5745 MT and sold 5396 MT of Poly-Iso-Butylene during the year 2000-01 as is conveyed in the Report of Directors addressed to Shareholders.

**E. VIEWS EXPRESSED BY EXPORTERS:**

5. M/s. Daelim Industrial Company limited, one of the exporters from Korea has submitted as under: -

- (a) There is no evidence that the domestic industry has suffered material injury. The exporter has claimed that they have quite a competitive advantage with the economy of scale, the quality of products and its own technology over the PIB producers in India. Therefore, the production cost of M/s. Daelim Poly-Iso-Butylene is lower than Indian producers. The exporter has submitted that 35% of Indian custom duty is for protecting local Poly-Iso-Butylene producers with small-scale plant. Their exporting price to India during the Period of Investigation was higher than production cost, around 6%. The net profit of 6% is normal in comparison with international business for commodity petrochemicals which has below 10% net profit generally Poly-Iso-Butylene is commodity chemical, not a specialty.
- (b) The Designated Authority determined that the petitioner was the lowest priced would result in significant loss to the domestic industry due to significantly lower prices quoted by the exporters in the tender floated by IOCL. According to the Article 2.1 of WTO ADA (Anti Dumping Agreement), the goods, which are introduced into the commerce of another country, are considered for anti dumping. Using tender price to calculate export price for goods which has not yet been introduced into the commerce of India may violate the Article afore mentioned.
- (c) The naphtha price during the Period of Investigation was increased around 42% compared to previous year. Therefore, the profit loss of petitioner was caused by just their high production cost with increase of feed stock price, not imported goods. Daelim also suffered from net profit loss at that time because international Poly-Iso-Butylene price was not increased.

**F. EXAMINATION BY THE AUTHORITY:**

6. The Designated Authority has considered all submissions made by the interested parties on merits and in accordance with the Rules. However, certain important issues raised by the petitioners/exporters and other interested parties have been examined by the Authority as under:-

- (i) With regard to the argument that domestic competition is reason of injury, the Authority notes that the argument is not only

unsubstantiated but also contrary to other submissions made by the consumers. It is argued by the consumers that the Domestic Industry is not in a position to meet the demand. In a situation where the demand is more than the domestic production the internal competition cannot cause injury.

- (ii) The Authority notes that the incidence of the Anti Dumping Duty has been restricted to lower of dumping margin and injury margin. While it is recognized that composition of the anti dumping duty may affect the price level of the product related competitiveness of the producers and consumers would not be very adversely affected, particularly when the amount of anti dumping duty has been restricted to what is considered to be absolutely necessary to address the injury to the Domestic Industry.
- (iii) With regard to the argument that offer made in a tender can not be used as the supplies were made beyond the investigation period and that the Rules provide for invoking action goods which have been imported into India, the Authority notes that anti dumping action can be invoked against goods "introduced into the commerce of the Country". The meaning of the word "introduced" can not be restricted to "imports in the investigation period". Firm and irrevocable offer made by a company in a tender tantamount to introducing the goods in the commerce of the Country. The Authority notes that as a result of such participation in the tender by the exporters and prices quoted by them, the Indian Producers have suffered injury, as the purchasers in such cases would place orders normally on the basis of lowest price quoted. It would be relevant to mention here that the offer made in the tender by the exporter at dumped prices has resulted in loss of contract to the Domestic Industry and has caused injury. The fact that the deliveries may be made outside the investigation period is of little relevance.
- (iv) With regard to the issue relating to cost inefficiency of the Domestic Industry as compared to other manufacturers of Poly-Iso-Butylene in India, the Authority examined the cost structure of the petitioner company in detail and a comparison of the cost of production of M/s. Kothari with M/s. Kochi Refineries was made. M/s. Kochi Refinery vide their letter dated 26.9.2001 had made the following submissions:
  - (a) Their Poly-Iso-Butylene plant made a net loss of about 40% of the total turn over of Poly-Iso-Butylene in the financial year 2000-2001

- (b) In spite of steep rise in the input cost during 2000 where as they were forced to reduce their price far below the cost of production so as to match the landed price of the imported product to sustain operation of the plant.
- (c) M/s.KRL was forced to reduce the prices by around 10% in the year 2000 to match with the prices offered by foreign vendors in the tenders floated by major oil industry company in India.
- (d) Their plant operation had to be stalled for nearly a month due to poor off take of the finished product in the year 2000.
- (v) In addition M/s. Kochi Refineries submitted the detailed break up of cost of production in format CI and CII which showed that the cost of production at M/s Kochi Refineries was substantially higher than the cost of production of Poly-Iso-Butylene at M/s. Kothari. However this information was insufficient to assess the Non Injurious Price. It was further observed that subsequent to this information, in the joint representation, the consumers submitted another set of costing information of M/s Kochi, which was found to be substantially different than claimed by M/s Kochi earlier. Evidently, cost claimed in the joint representation is not based on actual expenses incurred by M/s Kochi. The argument that cost of production is lower therefore, cannot be accepted
- (vi) The argument that the landed cost from Singapore is higher than the Non Injurious Price is factually incorrect since the landed price of exports from Singapore in the investigation period was US\$ \*\*\*\*\* which is lower than the Non Injurious Price determined by the Authority.
- (vii) With regard to the ability of the Domestic Industry to meet the demand it is clarified that the ability of the Domestic Industry to meet full demand is not a pre condition to recommendation of Anti Dumping Duty. The imports would continue at fair prices even after imposition of anti dumping duty. Imposition of Anti Dumping Duty would in no way affect the supplies of the product in the Indian Market.
- (viii) The Authority notes that it is not necessary that the dumping margin final assessed by the Authority cannot be more than the dumping margin claimed by the petitioners. The dumping margin determined by the Authority is based on the evidences collected by the Authority during the course of investigation

from all interested parties whereas the dumping margin assessed by the petitioners in the anti dumping petition is based on the information available with them.

- (ix) The Authority notes that the capacity shown in the Annual Report does not reflect an effective capacity of the petitioner. The Authority has found that the petitioner has the effective capacity of 7,500 MTs. The same has been considered not only for assessing the capacity utilisation for the Period of Investigation but also for the previous years.
- (x) With regard to the argument that there is an increase in the sales realization during the Period of Investigation as compared to the previous year and hence there is no price effect, the Authority notes that increase in selling price per se does not mean no injury as the increase in the selling price is to be seen alongwith in the increase in the cost of production. In the present case, the increase in the cost of production is more than increase in the selling price. The same has been claimed by other manufacturers of PIB namely M/s. Kochi Refineries Ltd. and M/s. IPCL.

7. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLES:**

- (a) The product involved in the present investigation is Poly-Iso-Butylene also known as PIB or Poly-Iso-Butene (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from European Union, Brazil, Japan, Korea RP, Singapore and Thailand. Poly-Iso-Butylene is a Synthetic Hydrocarbon Polymer manufactured by polymerization of C4 Olefins stream consisting mainly Iso-butene. Poly-Iso-Butylene finds application in various fields like Lube Oil additives, Cable Filling Compounds, Rubber Modifiers, Leather Chemicals, 2T Oil Formulations, Oil Insulators Adhesives etc. Present investigation covers all forms of Poly-Iso-Butylene.
- (b) Poly-Iso-Butylene is classified under Customs sub heading No. 3902 20 under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975

The Authority confirms the Preliminary Findings on product under consideration.

G. **LIKE ARTICLE:**

- 8. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules specifies that "Like Articles" means an Article which is identical or alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an Article, another article, having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

(a) **VIEWS OF IMPORTERS AND EXPORTERS:**

- (i) M/s Indian Additive Ltd., Chennai, one of the importers of the subject goods, has submitted on Like Article that they are importing HR Poly-Iso-Butylene ( Highly Reactive Poly Iso butylene). As per the importer HR Poly-Iso-Butylene and Poly-Iso-Butylene are entirely different from each other both physically and chemically. They have claimed that even the manufacturing technology is different and is not currently available to any of the Indian manufacturers.
- (ii) M/s Indian Additives Limited has further submitted that being the licensee under the technology agreement with Chevron Oronite to use their brand name (OLOA) (Oronite Lubricating Oil Additive) they are not allowed to use any raw material, which is not approved by them. Currently, only HR PIB is approved for manufacture of OLOA and is forbidden from using any other type of PIB. The importer has further stated that it is in their long term interest to use indigenously manufactured HR PIB as and when any Indian manufacturer is willing to step in. .

(b) **VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:**

- (i) There is no known difference in Poly-Iso-Butylene produced by the Indian industry and Poly-Iso-Butylene exported from the subject countries. Poly-Iso-Butylene produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Poly-Iso-Butylene produced by the petitioner is a like article to Poly-Iso-Butylene imported from the subject countries in accordance with the anti-dumping Rules.
- (ii) With regard to claim of BASF and Indian Additives Limited that they export/import HRPIB and the same is a different product, the Domestic Industry has submitted that the statement of the export/importer is incorrect. HR Poly-Iso-Butylene is nothing but a type of Poly-Iso-Butylene, which is product under consideration in the present investigation (the same has been imported in India). HR Poly-Iso-Butylene and Poly-Iso-Butylene are like article and the two are technically and commercially substitutable. The two have been technically and commercially substituted by the consumers in India. One of the importers, Indian Additives Limited was all along using PIB

produced by the domestic industry and is now using HR Poly-Iso-Butylene.

- (iii) Indian Additives Limited is understood to be importing HR Poly-Iso-Butylene due to their agreement with the supplier who has significant holding in Indian Additives Limited and not due to any issue concerning technical or commercial substitutability.
- (iv) The petitioners have claimed that the Poly-Iso-Butylene produced and sold by them and those imported from the subject countries are being used interchangeably by the customers in India.

9. **EXAMINATION BY THE AUTHORITY:**

In the Preliminary Findings the Authority held that Poly-Iso-Butylene being produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries has similar physical and chemical characteristics, product specification, functions and uses. Both can be used interchangeably and thus are commercially and technically substitutable and therefore, are like articles within the meaning of the Rules. With regard to HR PIB, the Authority notes that HR Poly-Iso-Butylene is a type of Poly-Iso-Butylene. The company using HR PIB was earlier using PIB. The company itself has claimed that they are using HR Poly-Iso-Butylene, as they are not allowed to use any other product by their foreign affiliate. It is not even the argument of the company that they cannot technically use Poly-Iso-Butylene. Moreover, the Domestic Industry is required to produce "like article" and not "identical article". The Authority, therefore, confirms the Preliminary Findings that the HR PIB and PIB are like article.

In view of the above, the Authority holds that the goods produced by the Domestic Industry are like article to the goods imported from the subject countries.

10. **DOMESTIC INDUSTRY:**

As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry." Further Rule 5(3) of the Anti Dumping Rules states that Designated Authority shall not initiate any investigations pursuant an application made under sub rule (1) unless it determines on the basis of an examination of the

degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the Domestic Industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the Domestic Industry.

11. **VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY:**

On the issue of standing of the Domestic Industry the petitioner have submitted that they account for a major proportion of Indian production of Poly-Iso-Butylene. Further, Kochi, one of the producers of the subject goods (who has also supported the petition and requested for imposition of anti-dumping duty) is a company related to one of the importers (BPCL). Hence, production of Kochi is required to be excluded from eligible production. M/s. IPCL (who is selling Poly-Iso-Butylene produced by MPL and GPL) has supported the petition. The petitioner, therefore, satisfies the standing of the Domestic Industry in accordance with the Rules.

12. **VIEWS OF IMPORTERS AND EXPORTERS:**

M/s Daelim, one of the exporters of subject goods from Korea has submitted that the petitioner has insisted that BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) should be excluded from the scope of the Domestic Industry for captive consumption. However, KRL (Kochi Refineries Limited) also participated in tender from HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited) on April, 2001 even though BPCL has acquired KRL on 2000. Therefore, the petitioner who represents below 25% of total Poly-Iso-Butylene production in India cannot be construed as Domestic Industry.

13. **EXAMINATION BY THE AUTHORITY:**

The petition has been filed by M/s. Kothari Sugars & Chemicals Limited, Manali, Chennai alleging dumping of the subject goods originating in or exported from EU, Brazil, Japan, Korea R.P., Singapore and Thailand. The petitioner accounts for more than 25% of the Domestic production during the Period of Investigation of the subject goods in India. The argument of M/s Daelim that the petitioner accounts for less than 25% of domestic production is factually incorrect. M/s Kochi Refineries Ltd., and M/s Indian Petrochemicals Corporation Ltd., (IPCL) have submitted their support to the petition for imposition of Anti Dumping Duty on the import of the subject goods from the subject countries. M/s Kochi Refineries and M/s Maharashtra Polybutene have even provided information relating to their cost of production. The Authority in the Preliminary Findings held that the

petitioner fulfils the requisite criteria to represent the domestic industry, as required under Rule 5(a) and (b) and Rule 2(b). In response to the Disclosure Statement of M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited has submitted that the representations made by M/s. Kochi Refinery Ltd. earlier were made by them as an individual manufacturer. With effect from 26<sup>th</sup> March, 2001 M/s. BPCL has taken control of M/s. KRL. However, the Authority holds that M/s. Kochi Refinery Ltd. is a separate legal entity and at no point of time during the course of investigation they have expressly withdrawn support to the petition.

Subsequent to the Preliminary Findings M/s Maharashtra Polybutene has also provided information relating to the cost of production through M/s IPCL. The Authority observes that the cost of production claimed by M/s Maharashtra Polybutene was higher than the cost of production claimed by the petitioner. However the same was not considered as the information submitted was insufficient for determining the Non Injurious Price. Accordingly, the Authority holds that the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition in terms of rule 5(3)(a) of the rules supra. The Authority also considers this petitioner company as Domestic Industry within the meaning of rule 2(b) supra.

#### H. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN:

14. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6) or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
  - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
  - (b) The cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-Section(6); Provided that in the case of import of the article from a

country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The Authority provided opportunity to the exporters from subject countries to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority wrote to the Embassies/High Commissions of subject countries in India also.

15. **TERRITORY OF EUROPEAN UNION:**

(a) **NORMAL VALUE:**

The Authority notes that none of the exporters/producers from the Territory of European Union have provided the information as per the prescribed questionnaire. M/s. Bayer, Germany has however offered comments, which have been considered in the Preliminary Findings

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for Final Findings. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Territory of European Union has been taken at US\$ \*\*\*\* per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Territory of European Union has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority had adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics in the Preliminary Findings. Ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to the extent of \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* and \*\*\*\* \$/MT respectively based on the claim of the petitioner has been considered. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to \*\*\*\* \$/MT

16. **BRAZIL**(a) **NORMAL VALUE:**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Brazil has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for Final Findings also. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Brazil has been taken at US\$ \*\*\*\* per MT

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Brazil has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority had adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics in the Preliminary Findings. Ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to the extent of \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* and \*\*\*\* \$/MT respectively based on the claim of the petitioner is has been considered. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to \*\*\*\* \$/MT

17. **JAPAN**(a) **NORMAL VALUE:**

The Authority notes that none of the exporters/producers from Japan has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority adopts the same for Final Findings. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Japan has been taken at US\$ \*\*\*\* per MT

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Japan has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. Based on the claim of the Petitioner the Authority has determined the weighted average export price on the basis of the prices offered by the exporters from Japan to M/s Indian Oil Corporation and the export statistics based on DGCI&S, Calcutta for the Period of Investigation. The Authority has adopted ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* and \*\*\*\* \$/MT respectively based on the claim of the petitioner. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to \*\*\*\* \$/MT

18 **KOREA R.P.**

**M/S. DAELIM CORPORATION, SEOUL, KOREA**

(a) **NORMAL VALUE**

The Authority notes that only one exporter/producer from Korea R.P. has provided the requisite information as per the prescribed questionnaire. M/s Daelim has provided invoice wise details of sales of the subject goods in Korea R.P. during the Period of Investigation. On the basis of the cost of production details claimed by the exporters, sales in the Domestic markets are above the cost of production and are therefore considered to be in the ordinary course of trade for the purpose of preliminary findings. For the Preliminary Findings the Authority had considered the adjustment as indicated by exporter/producer in their reply to the questionnaire. The Authority has considered the same for the Final Findings also. The weighted average Ex-factory domestic selling prices comes to \*\*\*\* US\$/MT in Period of Investigation.

(b) **EXPORT PRICE:**

The Authority notes that M/s Daelim has provided the transaction wise details of export sales to India of the subject goods during the Period of Investigation. The exporter/producer has indicated in the sales price structure for export to India various adjustment of export price viz. discounts/commission, packing, inland freight, ocean freight, shipping charges etc. The Authority for the purpose of preliminary findings had considered the adjustments as indicated by the exporter/producer. The Authority has considered the same for the purpose of Final Findings also. The weighted average ex-factory export price for the subject goods to India comes to \*\*\*\* \$/MT

19. **OTHER EXPORTERS/PRODUCERS OF KOREA R.P.**(a) **NORMAL VALUE**

As no other exporter/producer from Korea R.P. has provided the information, the Authority had adopted the weighted average domestic sales price as indicated by other cooperating exporter for assessing the normal value. The Authority has considered the same for the purpose of Final Findings also

(b) **EXPORT PRICE:**

The Authority has adopted the least of the export price to India as provided by the cooperative exporter from Korea R.P. without any adjustment on ocean freight, insurance, commission etc. The ex-factory export price in the Period of Investigation comes to \*\*\*\* US\$/MT.

20 **SINGAPORE**(a) **NORMAL VALUE .**

The Authority notes that the none of the exporters/producers from Singapore has provided the information as per the prescribed questionnaire

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority has adopted the same for Final Findings. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Singapore has been taken at US\$ \*\*\*\* per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Singapore has submitted details of export price in reply to the Questionnaire Based on the claim of the Petitioner the Authority has determined the weighted average export price on the basis of the prices offered by the exporters from Singapore to M/s Indian Oil Corporation and the export statistics based on DGCI&S, Calcutta for the Period of Investigation. The Authority has adopted ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* \*\*\*\* and \*\*\*\* \$/MT respectively based on

the claim of the petitioner. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to \*\*\*\* \$/MT.

21 **THAILAND**

(a) **NORMAL VALUE:**

The Authority notes that none of the exporters/producers from Thailand has provided the information as per the prescribed questionnaire.

The Normal Value was determined at the time of Preliminary Findings of the investigations on the basis of the constructed cost of production of Poly-Iso-Butylene as provided by the petitioner. The Authority has adopted the same for Final Findings. Accordingly, the Normal Value of Poly-Iso-Butylene for all exporters from Thailand has been taken at US\$ \*\*\*\* per MT.

(b) **EXPORT PRICE:**

None of the exporters from Thailand has submitted details of export price in reply to the Questionnaire. The Authority has adopted the export price based on DGCI&S, Calcutta statistics. Ocean freight, insurance, inland freight, port charges and commission to an extent of \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\*, \*\*\*\* and \*\*\*\* \$/MT respectively based on the claim of the petitioner. The Ex-factory export price in the Period of Investigation thus works out to \*\*\*\* \$/MT.

I. **DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE**

22. The rules relating to comparison provides as follows:-

- (a) "While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time.
- (b) Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sales, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability"

- (c) The Authority followed the consistent policy of adopting the principles governing the determination of Normal Value, Export Price, and Margin of Dumping as laid down in Annexure I of the anti dumping rules. Based on the Normal Values and Export Prices as indicated above the Authority assessed the Dumping Margins in case of all exporters from the subject countries as given in the table below:-

COUNTRY-WISE EXPORTERS/ PRODUCERS	NORMAL VALUE (\$/MT)	EXPORT PRICE (\$/MT)	DUMPING MARGIN (%)
<b><u>KOREA R.P.</u></b>			
(i) M/S.DAELIM CORPORATION LTD.,	****	****	15.72%
(ii) ALL OTHER EXPORTERS/PRODUCERS	****	****	46.29%
<b>ALL EXPORTERS/ PRODUCERS FROM</b>			
(i) TERRITORY OF EUROPEAN UNION	****	****	18.03%
(ii) BRAZIL	****	****	44.63%
(iii) JAPAN	****	****	57.23%
(iv) THAILAND	****	****	19.09%
(v) SINGAPORE	****	****	34.36%

The above Dumping Margins are above the de-minimus limits.

**J. INJURY AND CAUSAL LINK:**

23. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

- (i) In the case of imports from specified countries, the Designated Authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

- (ii) The Designated Authority shall determine the injury to Domestic Industry, threat of injury of Domestic Industry, material retardation to establishment of Domestic Industry and a causal link between dumped imports of injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure- II to these rules."

24. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

- (i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- (ii) While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 19 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.
- (iii) For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra

#### **K. CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY**

25. (a) Annexure II (iii) under Rule 11 supra further provides that "in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti Dumping investigation, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of

the like article or where the export of the individual country is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and cumulative assessment of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles”

- (b) The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limit prescribed above. Cumulative assessment of the effect of the imports from Territory of European Union, Brazil, Japan, Korea R.P., Singapore and Thailand are appropriate since the export prices from these countries were directly competing with the prices offered by the Domestic Industry in the Indian market and displacing domestic producers here.

26. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above such as production capacity utilisation, sales volume etc. have been examined as under -

(a) **QUANTUM OF IMPORTS AND MARKET SHARE:**

The information with regards to quantum of imports of Poly-Iso-Butylene has been based on information published by DGCI&S, Calcutta. The Authority notes that the market share of imports of the subject goods from the subject countries cumulatively was 73.60% during 1999-2000. The same has increased to 86.62% during the Period of Investigation. The total imports have increased by about 13% during the Period of Investigation over 1999-00.

(b) **PRODUCTION:**

The total production of petitioner company of subject goods during 1999-00 was 6111 MT decreased to 5648 MT (Annualised basis) during the Period of Investigation representing a decrease of about 7.58%.

(c) **SALES VOLUME:**

Total sales volumes of petitioner company during 1999-00 was 6392 MT, which decreased to 5217 MT (annualised basis) during the Period of Investigation showing a decrease of about 18.38%

(d) **CAPACITY UTILIZATION:**

The petitioner attained an average capacity utilisation of 81.48% in the year 1999-00, which decreased to 75.31% during the POI.

(e) **SALES REALISATION:**

The average sales realisation of petitioner companies from sale of subject goods in domestic market during the year 1999-00 was Rs. \*\*\*\* per MT, which increased to Rs. \*\*\*\* per MT in 2000-01 representing an increase of 5.26%. However the average sales realisation during the last five months of the period of investigation decreased to \*\*\*\*. This shows a steep decline of domestic sales realisation with in the Period of Investigation itself. However it has further been observed that the average Cost of Production of the subject goods has increased during the Period of Investigation over 1999-00 by Rs. \*\*\*\* per Mt. Accordingly the increase in sales realisation during the Period of Investigation has not compensated the increase in cost of production during the same period over the last year.

(f) **PROFITABILITY:**

It has been observed that the petitioner was earning a net profit of Rs. \*\*\*\* per MT of subject goods during 1999-00. However during the Period of Investigation, the petitioner incurred a loss of Rs. \*\*\*\* per MT from the subject goods.

(g) **EVIDENCE OF LOST CONTRACT**

The Domestic Industry would loose contracts due to significantly lower prices quoted by the exporters in the tender floated by M/s Indian Oil Corporation. Even the sole tender wherein the petitioner is lowest priced would result in significant loss to the Domestic Industry.

(h) **CLOSING STOCK**

Closing stock of the Domestic Industry during the Period of Investigation over 1999-2000 has increased from \*\*\*\* Mt to \*\*\*\* Mt. showing an increase of 351 %.

(i). **CASH FLOW**

The development of domestic industry's cash flow generated by the manufacturing activities of PIB is similar to the profitability of the domestic industry. Cash flow of the domestic industry have severely decreased with the erosion of the profits

(j). **RETURN ON INVESTMENTS**

The return on investment as a relation between the net profit of the domestic industry for PIB follow negative trend due to losses made by the domestic industry on each kg of product sold.

28384D/2002

(k) **FACTORS AFFECTING DOMESTIC PRICES:**

The landed value of imported material is significantly below the cost of production and fair selling price of the domestic industry causing price suppression and depression in the Indian market.

(l) **MAGNITUDE OF MARGIN OF DUMPING:**

The dumping margin from the subject countries is not only more than de minimus but also very significant. Therefore, the impact of dumping margin on the domestic industry is significant.

(m) **GROWTH**

The price at which the domestic industry has been forced to sell its produce are un-remunerative prices and domestic industry is making loss on each kg of PIB sold in domestic market. Therefore, the all petitioner company shows negative growth with regard to product under consideration.

(n) **WAGES**

Wages per employee of the domestic industry which were increasing, declined in the investigation period resulting into depression in the employees with regard to their future and employees are in search of newer employment. In this regard a representation has been received from the employees of the company.

(o) **EMPLOYMENT**

Employment levels of the domestic industry remains constant, however, losses to the domestic industry resulted into depression in the employees with regard to their future and employees are in search of newer employment.

From the above, it is evident that the domestic industry have suffered material injury from the dumped imports.

L. **CAUSAL LINK**

- 27.(a) In the Preliminary Findings the Authority after careful examination of the cost of production of the Domestic Industry and the landed value of the exports from subject countries noted that in case of Territory of European Union (EU), and Thailand the average landed value of exports during the Period of Investigation was more than the Non Injurious Price worked out for the Domestic Industry. Accordingly no causal link was established between the exports from these countries and the material injury caused to the Domestic Industry. The Authority

noted that Poly-Iso-Butylene has been exported to India from remaining countries namely, Brazil, Japan, Korea R.P. and Singapore at a price below its Normal Value. The Authority confirms its findings in this regard in the Final Findings also.

- (b) The Authority holds that the weighted average export price in US\$ terms from the subject countries as reported by the DGCI&S and as quoted in the tender floated by the Indian Oil Corporation has significantly declined. The petitioner company suffered a decline in sales price within the period of investigation itself inspite of increase in cost of production. The petitioner company was selling the subject goods at a profit earlier were able to sell the same in domestic market during the period of investigation only at substantial losses. In spite of decline in the selling price, the production and sales volumes of the Domestic Industry declined, as a direct result of imports from the subject countries. All these parameters cumulatively indicate that the petitioner company has suffered material injury and the injury to petitioner companies has been caused due to dumped imports of subject goods.

**M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:**

28. (a) The purpose of Anti Dumping Duties, in general, is to eliminate dumping which is causing injury to the petitioner company and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- (b) The Authority recognizes that the imposition of Anti Dumping Duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the Anti Dumping measures, particularly if the levy of the Anti Dumping Duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the petitioner company. On the contrary, imposition of Anti Dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the petitioner companies and help maintain availability of wider choice to the consumers of Poly-Iso-Butylene. Imposition of Anti Dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

N . **CONCLUSIONS:**

29 It is seen, after considering the foregoing, that:

- (a) Poly-Iso-Butylene originating in or exported from subject countries have been exported to India below Normal Value, resulting in dumping.
- (b) The Indian industry has suffered material injury on account price under-cutting, price suppression and significant increase in the volume of dumped imports of subject goods from Brazil, Japan, Korea R P and Singapore.
- (c) The injury has been caused cumulatively by the dumped imports from Brazil, Japan, Korea R.P. and Singapore.

30. It is considered necessary to impose definitive Anti-Dumping Duty, on all imports of Poly-Iso-Butylene originating in or exported from Brazil, Japan, Korea RP and Singapore .

31. It was considered whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury. The average landed price of the imports, for the purpose, was compared with the Non-injurious price of the petitioner company, determined for the period of investigation. Wherever the difference was less than the dumping margin, a duty lower than the dumping margin is recommended. Accordingly the Authority recommends definite Anti Dumping Duty equal to the difference between the amount indicated in column (2) below and the landed value of imports be imposed on all grades of subject goods originating in or exported from Brazil, Japan, Korea RP and

Singapore falling under Chapter 39 or any other Chapter of the Customs Tariff Act, 1975.

COUNTRY-WISE EXPORTERS/ PRODUCERS (1)	AMOUNT IN US\$ PER MT (2)
<b><u>KOREA R.P</u></b>	
(i) M/S.DAELIM CORPORATION LTD.,	1037.77
(ii)ALL OTHER EXPORTERS /PRODUCERS	1037.77
<b>ALL EXPORTERS/ PRODUCERS FROM</b>	
(i)TERRITORY OF EUROPEAN UNION	N.A
(ii)BRAZIL	1037.77
(iii)JAPAN	1037.77
(iv)THAILAND	N.A.
(v)SINGAPORE	1037.77

32. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except Additional duty of Customs levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
33. Subject to the above the Authority confirms the Preliminary Findings dated 12<sup>th</sup> December, 2001
34. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold(Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act. supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

